राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 289 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार ,23 अप्रैल 2021, मूल्य रु. 1.50

देश में 24 घंटे में मिले 3.14 लाख संक्रमित, 2014 मरीजों की मौत/ 1,78,841 मरीज ठीक भी हुए

ऑक्सीजन एवं दवाओं की कमी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र सरकार से जवाब

सीजेआई बोले- देश में राष्ट्रीय आपातकाल जैसे हालात

नई दिल्ली ■ एजेंसी

देशभर में कोरोना के रोज बढ़ते मामले और साथ में दवाओं-ऑक्सीजन के लिए मचे हाहाकार के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लेकर सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर यह पूछा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए उनकी क्या योजना है। हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। मौजूदा स्थिति को राष्ट्रीय आपातकाल के समान बताते हुए चीफ जस्टिस एसए बोबडे की खंडपीठ ने केंद्र से ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई और टीकाकरण को लेकर भी जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह कोरोना से लड़ने के लिए अपनी राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की योजना बताए। कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार बिंदुओं पर जवाब मांगा है। केंद्र ने कहा है कि सरकार ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी जवाओं की सप्लाई, टीकाकरण की प्रक्रिया और लॉकडाउन लगाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं...इन पर जवाब दे।

देश के छह हाईकोर्ट में हो रही है कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई

चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने इस दौरान यह भी कहा कि मौजूदा समय में देश के छह हाईकोर्ट में कोरोना से जुड़े मामलों की सुनवाई हो रही है। इसमें दिल्ली, बॉम्बे, सिक्किम, कलकत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने इतने हाईकोर्टों में सुनवाई को लेकर कहा कि इससे भ्रम पैदा हो रहा है। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी शुक्रवार को होगी। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को एमिकस क्युरी भी नियुक्त किया है।

दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई रोक रहे राज्य

केंद्र सरकार से बोला हाईकोर्ट

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना की दूसरी लहर के बीच दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी आ रही है। इस बीच, दिल्ली के सरोज सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ने ऑक्सीजन सपोर्ट की तुरंत मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अस्पताल ने याचिका दायर कर कहा है कि उसके यहां तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है और अस्पताल में 70 कोविड के गंभीर मरीज भर्ती हैं। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि समस्या यह है कि कुछ राज्यों द्वारा केंद्र के आवंटन का सम्मान नहीं किया जा रहा है। इन राज्यों का स्थानीय प्रशासन केंद्र द्वारा तय ऑक्सीजन आपूर्ति को रोक रहा है। अस्पताल ने याचिका में कहा कि वर्तमान में 70 मरीज गंभीर हैं व आईसीयू में हैं। 48 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और इनको तुरंत ऑक्सीजन का हाई फ्लो चाहिए। प्रतीक्षा सूची में 172 मरीज हैं, जिनमें से 64 उच्च ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता है। दिल्ली हाईकोर्ट में सरोज अस्पताल ने गुरुवार को याचिका दायर की है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन फर्म आईनॉक्स दिल्ली को ऑक्सीजन आपूर्ति जारी रखे और पानीपत संयंत्र हरियाणा को ऑक्सीजन आपूर्ति करे।

पीएम मोदी ने की उच्चस्तरीय बैठक

जमाखोरों से सख्ती से निपटे राज्य

अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। देश के अस्पतालों में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों से बेड फुल है तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होने से उन मरीजों का हाल बदहाल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑक्सीजन गाड़ियों के फ्री मूवमेंट के निर्देश दिए तो वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस पर गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक कर इसके समाधान पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह बताया गया कि बैठक में पीएम ने कहा कि जमाखोरों से राज्य सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए।

देश में कोरोना

- देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,14,835 नए मामले सामने आए, वहीं इस दौरान 2014 मरीजों की मौत हो गई।
- दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 306 मरीजों की मौत, वहीं संक्रमण के 26169 नए मामले आए।
- महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 67,013 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 568 की जान चली गई।
- मुंबई में पिछले 24 घंटे में 7,410 नए केस सामने आए हैं, हालांकि 75 मरीजों की मौत भी हो गई।
- उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 34379 नए केस, 195 मरीजों की मौत।
- गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकार्ड 13105 नए मामले सामने आए है इस दौरान 137 मौतें भी दर्ज की गई हैं।
- बिग बॉस 14 में नजर आ चुकी अभिनेत्री अर्शी खान कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है।
- कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को गुरुवार को मणिपाल अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
- खालसा साजना दिवस (बैसाखी) मनाकर पाकिस्तान से लौटे 437 पंजाबी तीर्थयात्रियों में से 80 यात्री कोरोना से संक्रमित पाए गए।
- दिल्ली के भाजपा नेता मनोज तिवारी संक्रमित।

पीएम मोदी ने बंगाल दौरा किया रद्द, आज शाम 5 बजे करेंगे वर्चुअल रैली

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना महामारी के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बंगाल में होने वाली अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी हैं। पीएम मोदी बंगाल में चुनाव प्रचार करने के बजाय शुक्रवार को कोरोना के हालात पर बैठक करेंगे। खुद उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वह शुक्रवार को कोरोना को लेकर एक हाईलेवल बैठक में शामिल होंगे, हालांकि, बंगाल भाजपा के अनुरोध पर पीएम मोदी बंगाल में शुक्रवार को शाम 5 बजे वर्चुअली रैलियों को संबोधित करेंगे।

18 वर्ष से ऊपर वाले वैक्सीन के लिए 28 अप्रैल से करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का अभियान एक मई से शुरू हो रहा है। इसमें 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए कोविन प्लेटफार्म और आरोग्य सेतु एप पर 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। इस आयु सीमा वाले लोग कोविन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी तक 18 साल से अधिक उम्र वालों को रजिस्ट्रेशन तारीख को लेकर अफवाह थी कि रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। MyGovIndia ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें, 24 अप्रैल से नहीं बल्कि 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी।

अमीरात एयरलाइंस का ऐलान, दुबई-भारत के बीच 10 दिनों तक नहीं चलेंगी फ्लाइट्स

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत में कोरोना की बेकाबू रफ्तार के चलते एक तरफ जहां ब्रिटेन ने इसे रेड लिस्ट में डाल दिया तो वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को अमीरात एयरलाइंस ने यह ऐलान किया कि वे दुबई और भारत के बीच चलने वाली उसकी सभी उड़ानें 10 दिनों तक नहीं चलेंगी। बयान में यह कहा गया कि 25 अप्रैल से अगले दस दिनों तक भारत और दुबई के बीच उनकी फ्लाइट्स नहीं चलेंगी। इधर, फ्रांस भी भारत से आने वाले पर्यटकों पर नए प्रवेश प्रतिबंध लगाने जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। इससे पहले ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली से आने वाले पर्यटकों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं।

टीकाकरण हुआ कम- रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में विगत 24 घंटे में 53,673 लोगों को टीका लगाया गया। यह संख्या बुधवार के मुकाबले अधिक है। बुधवार को 49 हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया गया था। विगत एक हफ्ते की बात करें तो 16 अप्रैल को सर्वाधिक टीकाकरण किया गया था। इस दिन 76,642 लोगों ने टीका लगवाया था।

एक नजर...

भारत ओपीसीडब्ल्यू में भारी बहुमत से विजयी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। रासायनिक शस्त्र निरोधन के लिए राष्ट्रों के सम्मेलन संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को आगामी तीन वर्ष के लिए बाय लेखापरीक्षक (एक्सटर्नल ऑडीटर) चुना है। विएना की राजधानी हेग में बुधवार को हुई संगठन की बैठक में बाय लेखापरीक्षक के चुनाव की प्रक्रिया में भारत को जबरदस्त समर्थन मिला और भारी बहुमत से कैग को इस दायित्व के लिए चुना गया। तीन वर्ष का कार्यकाल इसी वर्ष से शुरू होगा। यही नहीं, भारत को ओसीपीडब्ल्यू की 41 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का सदस्य भी चुना गया है। यह कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

बीएसएफ ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश

गुरदासपुर, (एजेंसी)। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में तैनात सीमा सुरक्षा बल की 121 वीं वाहिनी ने बुधवार की रात पठानकोट के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा पाकिस्तान की ओर से की जा रही घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि 21 और 22 अप्रैल की रात पठानकोट सीमा पर पाक की ओर से कुछ राष्ट्रविरोधी तत्व घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ सैनिकों ने उज्ह नदी के आगे संदिग्ध हलचल देखी। जवानों ने संदिग्धों पर गोली चलाई, जिसके पश्चात घुसपैठिए अंधेरे और गेहूं की फसल का लाभ उठाते हुए वापस पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए।

बीएसएफ जवान के कंधे पर आ बैठा पाक कबूतर

जालंधर, (एजेंसी)। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अग्रिम सीमा चौकी रोड़ावाला में एक पाकिस्तानी कबूतर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान के कंधे पर आ बैठा, जिसके पैरों में एक पर्ची बंधी हुई थी। बीएसएफ प्रवक्ता बीएस रावत ने गुरुवार को बताया कि 17 अप्रैल को एक कबूतर बीएसएफ के एक जवान के कंधे पर आकर बैठ गया, जिसके पैरों में एक पर्ची बंधी हुई थी। पर्ची में एक मोबाइल फोन नंबर लिखा हुआ था। उन्होंने बताया कि जांच के लिए सुरक्षा बल ने कबूतर को पुलिस के हवाले कर दिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कबूतर को वन विभाग को सौंप दिया है।

बंगाल में सात बजे तक 79.11 फीसदी मतदान

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा के छठे चरण में उत्तर 24 परगना जिले के बीजपुर निर्वाचन क्षेत्र में कुछ छिटपुट हिंसा को छोड़कर 43 सीटों पर शाम सात बजे तक 79.11 प्रतिशत मतदान हुआ। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि अभी तक पूर्वी वर्धमान में 75.20 फीसदी, उत्तर दिनाजपुर में 72.10, नादिया में 74 और उत्तर 24 परगना में 65.13 फीसदी मतदान हुआ है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। राज्य विधानसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह राज्य को 'दिल्ली के दो गुंडों' के सामने आत्मसमर्पण नहीं करा सकती।

मशहूर संगीतकार श्रवण राठौर का निधन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी नदीम-श्रवण में से जाने माने संगीतकार श्रवण राठौर का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी मृत्यु की जानकारी खुद उनके बेटे संजीव राठौर ने दी है। श्रवण बीते दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें मुंबई के एसएल राहेजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहीं गुरुवार को उन्होंने कोरोना से जंग लड़ते हुए अस्पताल में आखिरी सांस ली।

भारतीय मूल की वनीता गुप्ता ने अमेरिका में रचा इतिहास

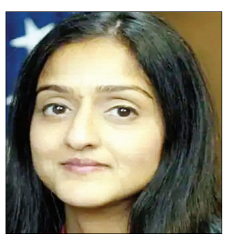

पहली भारतीय मूल की सहयोगी अटॉर्नी जनरल बनीं

वाशिंगटन ■ एजेंसी

अमेरिकी नागरिक अधिकारों की वकील वनीता गुप्ता ने पहली भारतीय मूल की सहयोगी अटॉर्नी जनरल बनकर इतिहास रच दिया है। उन्हें अमेरिका की संसद ने सहयोगी अटॉर्नी जनरल पद के लिए चुना है। न्याय मंत्रालय में तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज होने वाली वनीता पहली अश्वेत बन गई हैं। सीनेट में गुप्ता के पक्ष में 51 वोट पड़े, जबकि 49 सांसदों ने उनके खिलाफ मत डाले। रिपब्लिकन सीनेटर लीजा मुरकोवस्की ने खुद को अपनी पार्टी के रुख से अलग करते हुए गुप्ता के पक्ष में मतदान किया। इससे डेमोक्रेट्स के पाले में 51 मत आ गए और ऐतिहासिक रूप से गुप्ता के नाम की पुष्टि हुई।

बराबर मत पड़ने की सूरत में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपना वोट डालने के लिए सीनेट में मौजूद थीं। आपको बता दें कि अमेरिका में 100 सदस्यीय सीनेट में दोनों पार्टियों के 50-50 सदस्य हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि सहयोगी अटॉर्नी जनरल के तौर पर वनीता गुप्ता को चुने जाने पर बधाई। उन्होंने पहली अश्वेत महिला के रूप में इतिहास रचने का काम किया है। अब, मैं सीनेट से क्रिस्टन क्लार्क के नाम की भी पुष्टि करने की अपील करता हूं। दोनों बेहद योग्य हैं, अति सम्मानित वकील हैं, जो नस्ली समानता एवं न्याय को बेहतर बनाने के प्रति समर्पित हैं। गुप्ता पहली नागरिक अधिकार वकील भी हैं, जो न्याय मंत्रालय के शीर्ष तीन पदों में से एक पर सेवा देंगी।

सीनेट के बहुमत के नेता ने निभाई अहम भूमिका

सीनेट के बहुमत के नेता चक शूमर ने गुप्ता के नाम की पुष्टि में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि गुप्ता हमारी संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी में लंबे समय से अपेक्षित नजरिया लाएंगी। भारतीय आव्रजकों की बेटी गुप्ता फिलाडेल्फिया इलाके में जन्मी और पली-बढ़ी हैं। नागरिक अधिकारों की लड़ाई का उनका शानदार करियर रहा है। उन्होंने येल विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की और ज्यूरिस डॉक्टर की डिग्री न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से हासिल किया। गुप्ता ने 28 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत 'एनएएसीपी कानूनी बचाव कोष' से की थी। जहां उन्हें टेक्सास में 38 अश्वेत अमेरिकियों को नशीली दवाओं के मामलों में गलत तरीके से दोषी ठहराने के फैसलों को पलटने में सफलता मिली।

शिमला में बर्फबारी

इन दिनों हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि का दौर चल रहा है। गुरुवार को पहाड़ियों की रानी शिमला में भारी ओलावृष्टि के बाद सड़कें सफेद कंबल से ढक गई। जिस कारण स्थानीय तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार पर चुनाव आयोग ने लगाईं पाबंदियां

कोरोना के बढ़ते मामले पर रोड शो पर रोक रैली में नहीं होंगे 500 से ज्यादा लोग

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है।

बैन लगाने के साथ आयोग ने कहा कि कई राजनीतिक दल के उम्मीदवार सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी सभा में 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 रोधी नियमों के क्रियान्वयन को लेकर आयोग से नाराजगी जताई थी। हाईकोर्ट ने चुनाव के दौरान कोविड रोधी प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन का आग्रह करने वाली तीन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड सुरक्षा पर परिपत्र जारी करना और बैठकें करना पर्याप्त नहीं है तथा नियमों को लागू करने उठाए गए कदमों के संबंध में शुक्रवार तक शपथ पत्र दायर किया जाना चाहिए। हम रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री से संतुष्ट नहीं हैं कि बंगाल में भारत निर्वाचन आयोग और इसके अधिकारियों ने अपने परिपत्र जारी किए हैं।

बचे हैं दो और चरण

बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव कुल 8 चरणों में कराया जा रहा है। गुरुवार को मिलकर कुल छह चरणों के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। अब केवल दो चरणों के लिए मतदान बचे हुए हैं। इनमें सातवें चरण के लिए 26 अप्रैल और आखिरी और आठवें चरण के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा।

एक वैक्सीन के 3 दाम कैसे? फ्री टीके देने से बच रही सरकार

सोनिया का पीएम मोदी को पत्र, बोलीं

नई दिल्ली ■ एजेंसी

भारत सरकार ने आने वाले दिनों में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाने की घोषणा की है। इसको लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सोनिया ने पत्र में केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। पत्र में सरकार की नीति को मनमाना और भेदभावपूर्ण करार देते हुए बदलाव की मांग की गई है। सोनिया गांधी का आरोप है कि कोरोना टीका की नई नीति के जरिए केंद्र सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लिया है।

दरअसल, सीरम इंस्टीट्यूट ने बीते दिन अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के दाम जारी किए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग-अलग दाम तय किए गए हैं। सीरम ने जो रेट लिस्ट जारी की है, उसके मुताबिक राज्य सरकार को 400 रुपए प्रति डोज, प्राइवेट अस्पताल को 600 रुपए प्रति डोज और और केंद्र सरकार को 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। पीएम मोदी को लिखे पत्र में सोनिया ने सवाल उठाया है कि वैक्सीन के अधिक दामों से राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ेगा और आम आदमी को वैक्सीन के लिए अधिक पैसा देना होगा। ऐसे में एक ही वैक्सीन निर्माता तीन तरह के रेट कैसे तय कर सकता है।सोनिया ने पत्र में आगे लिखा है कि कांग्रेस ने पहले ही इसकी मांग की है कि इस नीति का पुनर्मूल्यांकन किया जाए।

अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर लगी अस्थाई रोक

श्रीनगर ■ एजेंसी

देश में कोरोना एक बार फिर डरावनी रफ्तार के साथ फैल रहा है। पिछली बार की तुलना में कोरोना का संक्रमण करीब तीन गुणा अधिक रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। इसकी वजह से देश के अधिकतर कोविड-19 अस्पतालों में मरीजों के बेड फुल हो चुके हैं और स्थिति काफी भयावह हो चुकी है।

कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर अस्थाई रोक लगा दी गई है। अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड ने कहा कि वे पूरे मामले पर बेहद करीबी नजर बनाए हुए हैं और स्थिति सुधरने पर दोबारा खोल दिया जाएगा। देश में एक दिन में सामने आए 3 लाख 14 हजार 835 नए मामलों में से 75 फीसदी मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात समेत 10 राज्यों में आए हैं। इन 10 राज्यों की लिस्ट में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में सर्वाधिक 67,468 मामले सामने आए जो देश में सक्रमण के कुल मामलों का 14.38 प्रतिशत है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 33,106 जबकि दिल्ली में 24,638 नए मामले सामने आए। देश में 22,91,428 मरीज अब भी संक्रमण की चपेट में हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 14.38 प्रतिशत हैं।

ऑक्सीजन के निर्बाध आपूर्ति के लिए आपदा प्रबंधन कानून लागू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राज्यों में ऑक्सीजन की कमी देखते केंद्र सरकार ने इसके निर्बाध उत्पादन और आपूर्ति के लिए कठोर आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया है।

केंद्र ने गुरुवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे चिकित्सकीय ऑक्सीजन का निर्बाध उत्पादन-आपूर्ति और उसका अंतर्राज्यीय परिवहन तय करें। इस आदेश की अवहेलना होने पर संबंधित जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जवाबदेह होंगे। कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या से ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि के बाद कुछ राज्यों द्वारा अन्य राज्यों को चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित करने की खबरों को देखते केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कठोर आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के तहत यह आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मध्य और गंभीर लक्षण वाले मरीजों के इलाज के लिए चिकित्सकीय ऑक्सीजन की पर्याप्त और निर्बाध उपलब्धता महत्वपूर्ण है।

प्राथमिकता — कार्बन मुक्त बनेगी भारत की अर्थव्यवस्था

केंद्रीय मंत्री बोले- सरकार ने बनाया खास प्लान

नई दिल्ली ■ एजेंसी

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि भारत की प्राथमिकताएं विकसित देशों की दुनिया के मुकाबले अलग हैं, इसके बावजूद वह एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक होने के नाते अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने एक अमेरिकी 'थिंक टैंक' से कहा कि आने वाले समय में भारत से ही ऊर्जा मांग की वृद्धि आएगी, क्योंकि आने वाले वर्षों में भारत की ऊर्जा मांग बढ़नी तय है।

प्रधान ने कहा कि भारत की ऊर्जा मांग में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ही आगे होगा। इस संबंध में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल में की गई घोषणा का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत की ऊर्जा टोकरी में उसकी जरूरत में 40 प्रतिशत हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से पूरा होगा।

उभरती हुई अर्थव्यवस्था है भारत

सेंटर फार स्ट्रेटजिक एण्ड इंटरनेशनल स्टडीज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि हम एक उभरती अर्थव्यवस्था हैं। हमारी प्राथमिकताएं और रणनीति दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले अलग है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक होने के नाते भारत अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन मुक्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवसथा से है जहां कार्बन उत्सर्जन करने वाले कम ऊर्जा स्रोत हों, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कम से कम गैस उसमें निकले।

भारतीय अमेरिकी वनिता गुप्ता बनीं एसोसिएट अटार्नी जनरल, अमेरिकी सीनेट ने दी मंजूरी

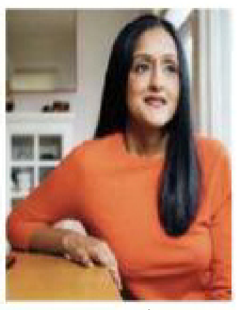

वाशिंगटन। ओबामा प्रशासन के दौरान जस्टिस डिपार्टमेंट में अपनी सेवा दे चुकी भारतीय मूल की वनिता गुप्ता को एसोसिएट अटार्नी जनरल नियुक्त किया गया है। उनके नाम पर अमेरिकी सीनेट में स्थानीय समयानुसार बुधवार को मुहर लगाई गई। बता दें कि इस पर पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की नागरिक होने का सम्मान भी वनिता को ही मिल रहा है। खबर के अनुसार, वनिता गुप्ता के नाम पर सीनेट में वोटिंग हुई और 51-49 के अंतर से उनके नाम को मंजूरी मिली है।

रिपब्लिकन लिसा मुर्कोव्स्की ने बाइडन के उम्मीदवार के पक्ष में अपना वोट दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि वनिता गुप्ता निजी तौर पर अन्याय का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध रही हैं। वोटिंग से पहले राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि उन्होंने 'बहुत ही दक्ष और सम्मानित' भारतीय मूल की वकील वनिता गुप्ता को नामित किया है, जिन्होंने अपना पूरा करियर नस्लीय समानता और न्याय की लड़ाई में लगाया है।

राष्ट्रपति बाइडन ने कहा,'मैंने न्याय विभाग में दो अहम पदों के लिए वनिता गुप्ता और क्रिस्टेन क्लॉर्क को नामित किया जो बहुत ही दक्ष और सम्मानित वकील हैं और जिन्होंने अपना पूरा करियर नस्लीय समानता और न्याय की लड़ाई में लगाया है।' अमेरिकी सीनेट में वनिता गुप्ता के नाम पर वोटिंग पिछले सप्ताह ही होना था लेकिन रिपब्लिकन की ओर से इसका विरोध किया गया था क्योंकि रिपब्लिकनों की आलोचना करते हुए हाल में ही वनिता गुप्ता ने कुछ ट्वीट किए थे। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट में तीसरा सबसे ऊंचा पद एसोसिएट अटॉर्नी जनरल का होता ह। इस डिपार्टमेंट में एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के तौर पर वनिता गुप्ता नागरिक अधिकारों के काम की निगरानी में अहम भूमिका निभाएंगी।

पाकिस्तान में वरिष्ठ पत्रकार पर किया गया जानलेवा हमला, गोली मारकर घायल किया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सेना के सत्ता में दखल के विरोधी पत्रकार अबसर आलम (50) को गोली मारकर घायल कर दिया गया है। हमलावर की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पत्रकार आलम पर हमला राजधानी इस्लामाबाद के एक पार्क में हुआ, जहां वह टहलने गए थे। वह नवाज शरीफ के सत्ताकाल में करीब दो साल पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्यूलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन रहे थे। बाद में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में पाकिस्तान की एक अदालत ने उन्हें हटाने का आदेश दिया था। आलम ने इसके लिए सेना पर साजिश रचने का आरोप लगाया था।

पुलिस के अनुसार आलम की पसलियों में गोली लगी है और अब वह खतरे से बाहर हैं। गोली लगने के बाद दिए बयान में आलम ने कहा, उन्होंने कभी भी अपना हौसला नहीं खोया और न ही भविष्य में हौसला खोएंगे। वह इसी तरह से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि 2018 में इमरान खान के सत्ता संभालने के बाद से पाकिस्तान में पत्रकारों पर हमले बढ़े हैं और उनका काम करना मुश्किल हुआ है।

बढ़ते कोरोना के कारण अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए चौथे स्तर का हेल्थ नोटिस जारी किया

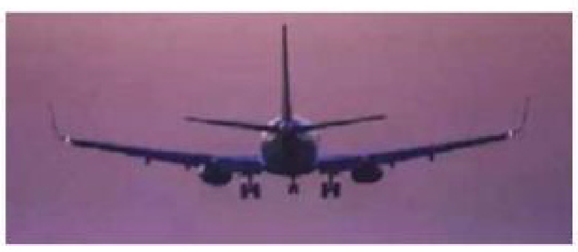

वाशिंगटन। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए चौथे स्तर का हेल्थ नोटिस जारी किया है। अमेरिकी सीडीसी के परामर्श के अनुसार, भारत यात्रा परामर्श के चौथे स्तर में है। अमेरिका ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर यहां की यात्रा नहीं करने को कहा है। अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत के लिए चैथे स्तर का यात्रा स्वास्थ्य नोटिस जारी किया है, जो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के उच्च स्तर का संकेत देता है। सीडीसी ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय को इस बारे में सूचित किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भारत ही नहीं मित्र देश भी पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा है कि बढ़ते संक्रमण को लेकर अमेरिका भी चिंतित है और हर रोज की स्थिति को गहनता से देख रहा है। भारत में बढ़ते कोरोना मामलों पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि सोमवार को विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की इसी मुद्दे पर विस्तार से वार्ता हुई है। नेड प्राइस ने कहा कि भारत मित्र देश है हमसे जो संभव होगा, वह करेंगे। इस वायरस का नियंत्रण में रहना जरूरी है। इसी में सभी देशों की भलाई है। फिलहाल अमेरिकी नागरिकों को भारत की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। ज्ञात कि पूरे कोरोना काल के दौरान भारत ने जिस देश पर संकट आया, सभी देशों की भरपूर मदद की है। सीडीसी ने आगे कहा- 'वैसे अमेरिकी नागरिकों को जो जिन्हें भारत की यात्रा करनी ज्यादा जरूरी है, उनसे यात्रा से पहले पूरी तरह से टीकाकरण प्राप्त करने का आग्रह किया जाता है और अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा के उपायों को जारी रखने के लिए कहा जाता है।

कोरोना दुनिया में:पहली बार 24 घंटे में रिकॉर्ड 8.80 लाख से ज्यादा नए केस; एशियन देश अब सबसे ज्यादा प्रभावित

न्यूयार्क। दुनियाभर में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। लगभग सभी देशों में कोरोना के नए मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते दिन दुनिया में रिकॉर्ड 8 लाख 80 हजार 977 मामले सामने आए। यह कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 7 और 8 जनवरी को 8.43 लाख नए केस सामने आए थे।

कोरोना का सबसे ज्यादा प्रभाव एशियन देशों पर पड़ा है। यहां के करीब 15 देशों में हालात बेकाबू हो गए हैं। भारत में नए संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं, तुर्की में रोजाना 60 हजार और ईरान में 24 हजार नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे ही अन्य एशियाई देशों में भी रोजाना मिलने वाले संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।

बीते दिन 14 हजार से ज्यादा मौतें

दुनिया में 14,088 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। सबसे ज्यादा 3157 मौतें ब्राजील में रिकॉर्ड की गईं। इसके बाद 2102 मौतें भारत में और 876 मौतें अमेरिका में हुईं। पोलैंड में 740 और मैक्सिको में 582 मौतें हुईं।

10 देशों में कोरोना की चौथी लहर

भारत कोरोना की दूसरी लहर से परेशान है तो दुनिया के 10 ऐसे भी देश हैं, जहां संक्रमण की चौथी लहर चल रही है। इनमें ब्राजील, तुर्की, फ्रांस, अर्जेंटिना, ईरान, कोलंबिया, जमर्नी, इटली, पेरू और पोलैंड जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में हर दिन 10 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। सबसे खराब हालत ब्राजील और तुर्की की है।

ब्रिटेन में वैक्सीनेशन के बाद घटी मौतें

कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान ने दुनिया में असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसका ताजा उदाहरण ब्रिटेन में देखने को मिला है। 7 सितंबर को वहां 3 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मौतों का आंकड़ा धीरे-धीरे बढ़ता गया। पर टीकाकरण शुरू होने के बाद अब वहां महामारी से सिर्फ 4 मौतें दर्ज हुई हैं, इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की दर पिछले सोमवार के मुकाबले 70त्न घट गई है। इसके अलावा ब्रिटेन में नए कोरोना मरीजों की रफ्तार भी करीब 17फीसदी कम हुई है।

अब तक 14.26 करोड़ संक्रमित

दुनिया में अब तक 14 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 30 लाख 71 हजार मरीजों की मौत हो चुकी है। 12.22 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 1.87 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें एक लाख 9 हजार 845 मरीजों की हालत क्रिटिकल है और 1.86 करोड़ लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं।

पाकिस्तान में ब्लास्ट: बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के होटल में धमाका, 5 लोगों की मौत

सेना भेजने की तैयारी

क्वेटा। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में रात करीब 11 बजे एक बड़ा धमाका हुआ। यह ब्लास्ट क्वेटा के सबसे बड़े होटल सेरेना की पार्किंग में हुआ।

अब तक पांच लोगों के मारे जाने की खबर है। जिस होटल में ब्लास्ट हुआ, यहां चीन के अधिकारी रुके थे। शहर के सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर के मुताबिक, मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर घायलों की हालत गंभीर है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शहर के बड़े हिस्से को सेना के हवाले करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि यहां बीते कई दिनों से हिंसा हो रही है।पाकिस्तान के अखबार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के मुताबिक, घटना के वक्त पार्किंग में कई लोग लोग एक साथ झुंड बनाकर बातचीत कर रहे थे।

मौजूद थे। ये लोग यहां एक फंक्शन में शामिल होने आए थे। इनमें से कुछ विदेशी नागरिक भी थे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि करीब 33 लोग घायल हैं और इनमें से ज्यादातर की हालत गंभीर है। इसकी वजह ये है कि ज्यादातर

बम धमाका या कुछ और

बलूचिस्तान में लंबे वक्त से आजादी की मांग उठ रही है। यहां विद्रोही गुट आए दिन पाकिस्तानी फौज की चौकियों पर हमले करते हैं और इनमें कई सैनिक मारे जा चुके हैं। हाल के दिनों में यहां रेंजर्स और स्पेशल बटालियन की तैनाती भी की गई है। इसके बावजूद हिंसा कम नहीं हुई।

धमाके में सात कारें पूरी तरह तबाह हो गईं। अब तक यह साफ नहीं हो सका है कि यह बम धमाका था या कुछ और। बलूचिस्तान सरकार ने ब्लास्ट की पुष्टि करते हुए मरने वालों का आंकड़ा 4 बताया। सरकार के बयान में कहा गया- यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह आतंकी हमला है या कुछ और। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने भी घटना की पुष्टि की। कहा- हम मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। आतंकवाद से निपटने के लिए पूरा मुल्क एकजुट है।

सीरिया ने इजरायल के परमाणु रिएक्टर के पास दागी मिसाइल, इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई

यरुशलम। सीरिया की तरफ से इजरायल पर गुरुवार तड़के दागी गई मिसाइल के कारण देश के टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर रिएक्टर में सायरन बजने लगे। इजरायल की सेना ने इसकी जानकारी दी। इस घटना के सामने आने के बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया में स्थित मिसाइल लॉन्चर और एयर-डिफेंस सिस्टम पर हमला किया है। हाल के दिनों में गाजा पट्टी की तरफ से भी इजरायल पर मिसाइलें दागी गई हैं। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा पर नियंत्रण रखने वाले हमास के कई ठिकानों पर हमला किया।

ये घटना हाल के वर्षों में इजरायल और सीरिया के बीच हुई सबसे हिंसक घटनाओं में से एक है। घटना को लेकर इस बात के संकेत हैं कि इसमें ईरान की भूमिका भी थी। ईरान के सैनिक सीरिया में मौजूद हैं और उसने यहां पकड़ बनाई हुई है। तेहरान अपने परमाणु फैसिलिटी पर हुए हमलों के लिए लगातार इजरायल

पर आरोप लगा चुका है। सबसे ताजा मामला 11 अप्रैल का है, जब ईरान के नन्ताज परमाणु फैसिलिटी में तोड़-फोड़ की गई। इसका आरोप भी ईरान ने इजरायल पर लगाया और बदला लेने की कसम खाई। ईरान ने अमेरिकी नेतृत्व के साथ चल रहे अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के प्रयासों को जटिल करने की धमकी भी दी।

इमरान का नया पैंतरा: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमिताभ की फिल्म इंकलाब की क्लिप शेयर की, कहा-

इसी तरह साजिश रच रहा है माफिया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का तीन दिन में दूसरी बार सोशल मीडिया पर मजाक उड़ रहा है। इस बार उन्होंने अपने खिलाफ साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए बॉलीवुड की फिल्म इंकलाब का क्लिप शेयर किया। इसमें कादर खान अपनी पार्टी के नेताओं को सत्ता पाने के गलत रास्ते बताते नजर आते हैं। इमरान का आरोप है कि भ्रष्ट माफिया पहले दिन से उनकी सरकार गिराने के लिए इसी तरह की साजिश रच रहा है।

पायरेटेड प्रिंट

इमरान ने सोशल मीडिया पर यह क्लिप शेयर की। कुछ ही देर में पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हसन जैदी ने इमरान को टैग करते हुए बताया कि यह पायरेटेड प्रिंट से लिया गया क्लिप है। कुछ और पत्रकारों ने भी इसी तरह के रिएक्शन दिए। क्लिप शेयर करते हुए इमरान ने कैप्शन में लिखा- इसी तरह की साजिशें मेरी सरकार के खिलाफ पहले दिन से की जा रही हैं। यह करप्ट माफिया की करतूत है।

1984 में आई थी अमिताभ की इंकलाब

इमरान ने बॉलीवुड की फिल्म इंकलाब का क्लिप शेयर किया। यह फिल्म 1984 में रिलीज हुई। फिल्म में अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और कादर खान अहम भूमिकाओं में थे। क्लिप में कादर खान अपनी पार्टी के नेताओं की एक मीटिंग लेते नजर आते हैं। इसमें वो नेताओं को बताते हैं कि सत्ता पाने के लिए किस तरह के गलत कदम और षडयंत्र किए जाते हैं। कादर खान कहते हैं- लोगों में डर पैदा करने के लिए काम करो। सरकार के खिलाफ नाराजगी पैदा करो। इसके रास्ते भी बताए जाते हैं। कुछ देर बाद ही यह पोस्ट सोशल मीडिया से हटा ली गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इमरान का मजाक उड़ा रहे थे।

कई बार उड़ चुका है मजाक

इमरान को प्रधानमंत्री बने करीब तीन साल हो चुके हैं। इस दौरान कई बार वे मजाक का पात्र बने। पिछले साल एक भाषण में जर्मनी को जापान का पड़ोसी बता दिया था। पिछले दिनों संसद में नवाज शरीफ पर उन्होंने कई आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने इस्लाम की रक्षा के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इमरान के मुताबिक, नवाज 1988 में प्रधानमंत्री बने थे, जबकि सच्चाई यह है कि नवाज ने पहली बार 1990 में प्रधानमंत्री बने थे।

अमेरिका में पुलिस ने अश्वेत किशोरी को मार डाला, ओहियो में सड़कों पर विरोध प्रदर्श

वाशिंगटन। अमेरिका के ओहियो में कोलंबस पुलिस ने एक अश्वेत किशोरी को गोलियों से भून डाला। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस द्वारा जारी वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि किशोरी चाकू लेकर दो लोगों पर कूद पड़ी थी। इस घटना के खिलाफ लोग ओहियो के सबसे बड़े शहर की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने निकल पड़े। यह घटना ऐसे वक्त हुई जब पूरे देश का ध्यान जार्ज फ्लायड हत्या मामले में अदालत के फैसले की तरफ लगा था। मृत किशोरी की पहचान माखिया ब्रायंट के रूप में हुई है।

किशोरी ने दो महिलाओं पर की थी चाकू से हमले की कोशिश

घटना का वीडियो जारी करते हुए कोलंबस के अंतरिम पुलिस प्रमुख माइकल वुड्स ने कहा कि पुलिस को आपातकालीन नंबर-911 पर एक काल आई थी। इसमें कहा गया था कि शहर के दक्षिण-पूर्वी इलाके में एक घर पर चाकू से हमला करने की कोशिश हुई है। पुलिस वहां पहुंची तो अफरा-तफरी का माहौल था। एक किशोरी ने चाकू लहराते हुए एक महिला पर हमला किया। वह पीछे की तरफ गिर पड़ी तो किशोरी ने दूसरी महिला पर हमला कर दिया।

वीडियो को धीरे-धीरे चलाने पर देखा जा सकता है कि दूसरी महिला पार्किंग में खड़ी एक कार पर गिर पड़ी। इसके बाद किशोरी ने फिर उस पर हमला करने के लिए हाथ उठाया। लेकिन इसी बीच पुलिस अधिकारी ने उसे गोली मार दी। गोली लगते ही वह वहीं ढेर हो गई। उसके पास से रसोई घर में काम आने वाला एक चाकू बरामद हुआ।

ज्ञात हो कि पिछले साल अफ्रीकी अमेरिकी अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में कोर्ट ने पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन को

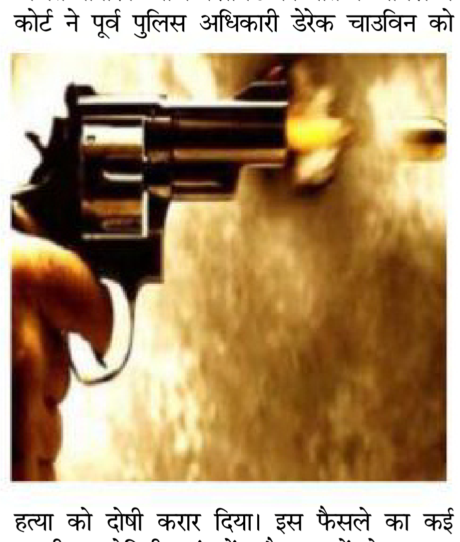

हत्या को दोषी करार दिया। इस फैसले का कई भारतीय-अमेरिकी सांसदों और समूहों ने स्वागत किया है। चाउविन द्वारा फ्लॉयड की गर्दन को घुटने से दबाये जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

अमेरिकी आयोग ने की भारत को 'विशेष चिंता वाला देश' घोषित करने की सिफारिश

वाशिंगटन। अमेरिका की संसद द्वारा गठित अर्ध न्यायिक निकाय 'अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग' (यूएससीआइआरएफ) ने बाइडन प्रशासन से भारत समेत चार देशों को 'विशेष चिंता वाले देश' घोषित करने की सिफारिश की है। आयोग का आरोप है भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति 2020 में भी नकारात्मक बनी रही।आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय से 10 देशों को फिर से 'विशेष चिंता वाले देश' घोषित करने की मांग की है। इन देशों में म्यांमार, चीन, इरीट्रिया, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। आयोग ने भारत के अलावा रूस, सीरिया और वियतनाम को भी 'विशेष चिंता वाले देश' घोषित करने की सिफारिश की है। हालांकि आयोग की यह रिपोर्ट बाइडन प्रशासन के लिए बाध्यकारी नहीं है। भारत अतीत में कह चुका है कि यूएससीआइआरएफ उन मामलों पर भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार करता है जिस पर उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने पिछले साल कहा था कि किसी विदेशी निकाय को देश के नागरिकों के संविधान के तहत सुरक्षित अधिकारों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है।खास बात यह है कि अन्य देशों के विपरीत यूएससीआइआरएफ की भारत के बारे में की गई सिफारिशें सर्वसम्मत नहीं हैं।

महंगी पड़ रही है बेहद धीमी टीकाकरण की रफ्तार: जापान में कोरोना बेकाबू

- आपातकाल लगा तो टल सकते हैं ओलिंपिक खेल, आबादी 12 करोड़ से अधिक, टीके 21 लाख को भी नहीं लगे हैं

टोक्यो। दुनिया में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक साबित होती जा रही है। जापान में बढ़ते हुए कोरोना केसों को देखते हुए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। जापान के पीएम ने इस माह के अंत में होने वाली भारत और फिलीपींस की यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। पीएम सुगा का फोकस जापान में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने पर है।टोक्यो, ओसाका और ह्योगो प्रांत में हालात बिगड़ रहे हैं।

जापान में बेहद धीमी वैक्सीनेशन रफ्तार के कारण यह स्थिति बन रही है। ब्लूमबर्ग वैक्सीन ट्रैकर के अनुसार, जापान में 20 लाख 54 हजार 880 लोगों को टीका लगा है। जबकि, देश की आबादी 12 करोड़ 61 लाख के करीब है। वहां 1फीसदी लोगों को पहली डोज और 0.6त्न लोगों को दोनों डोज लगी हैं।

संक्रमण के कारण 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलिंपिक खेलों के आयोजन पर भी संकट है। प्रांतों के गर्वनरों ने आपातकाल लगाने की मांग की है। टोक्यो में 29 अप्रैल से 9 मई तक आपातकाल लग सकता है, यहां अब तक 13 लाख से अधिक मरीज और 1,850 मौतें दर्ज हुई हैं।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि सितंबर-दिसंबर के मध्य कोरोना से बचाव की गोली आ जाएगी। इससे अस्पताल में भर्ती नहीं

होना होगा, बस घर पर गोली खानी होगी। एंटीवायरल टास्कफोर्स का गठन कर गोली विकसित की जा रही है। अमेरिकी राज्य हवाई में 11 मई से वैक्सीन पासपोर्ट लागू किया जाएगा। न्यूयॉर्क के बाद इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य है। इस पासपोर्ट के तहत व्यक्ति को यात्रा के दौरान न तो कोरोना संबंधी जांच से गुजरना होगा और न ही उसे क्वारंटीन होना होगा। टीका लगने की जानकारी इसमें दर्ज होगी। ब्राजील, तुर्की, फ्रांस, अर्जेंटिना, ईरान, कोलंबिया, जमर्नी, इटली, पेरू और पोलैंड जैसे देशों में हर दिन 10 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। साथ ही इन देशों मे कोरोना की चौथी लहर चल रही है। संक्रमण की रफ्तार बैकाबू होने के कारण ब्राजील और तुर्की की हालत सबसे खराब है।

कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण भारत से आने वाले यात्रियों पर फ्रांस लगाएगा प्रतिबंध

पेरिस। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण फ्रांस भारत से आने वाले यात्रियों पर नए प्रवेश प्रतिबंध लगाएगा। ये प्रतिबंध उनके अतिरिक्त होंगे, जिनकी घोषणा ब्राजील, अर्जेंटीना और चिली समेत चार देशों के संबंध में की गई थी। प्रतिबंध शनिवार से लागू होंगे।

सरकारी प्रवक्ता गैब्रियल अट्टल ने बताया कि योजना के मुताबिक फ्रांस तीन मई से घरेलू यात्रा पर लागू प्रतिबंधों को हटा लेगा, लेकिन शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। अप्रैल की शुरुआत से लागू आंशिक लॉकडाउन में बंद चल रहीं गैरजरूरी दुकानें अभी मई के मध्य तक नहीं खुलेंगी।काठमांडु, एएनआइ। किसी तीसरे देश की यात्रा के लिए भारतीय पासपोर्ट (स्पष्ट आव्रजन स्टैंप के साथ) पर हवाई मार्ग से नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों को 22 अप्रैल से 19 जून के बीच अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की जरूरत नहीं होगी। दूतावास ने बुधवार को बताया कि तीसरे देश की यात्रा के लिए जमीनी मार्ग या पहचान पत्र के साथ हवाई मार्ग से नेपाल जाने वाले भारतीय नागरिकों को भारतीय दूतावास से एनओसी जरूरी होगी। इस बदलाव के बारे में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आव्रजन अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।

'दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी'

ऑक्सीजन को लेकर हो रही खींचतान को खत्म करने का किया आग्रह

नई दिल्ली (आनंद राय)। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार से दिल्ली में ऑक्सीजन की नियमित सप्लाई पर ध्यान देने और अन्य राज्यों द्वारा दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई में हस्तक्षेप को रोकने पर उचित कदम उठाने की मांग की। और केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि दिल्ली में हरियाणा और उत्तरप्रदेश से आने वाले ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए जरूरत होने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की जाए। और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जो जंगलराज चल रहा है उसे खत्म किया जाए वरना हालात खराब होते चले जाएंगे।

आपूर्ति के रुकने से भयावह हो जाएंगे हालात : मनीष सिसोदिया

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कल केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के साथ-साथ बाकी राज्यों का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया गया। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्लांटों में वहां के अधिकारी दिल्ली की ऑक्सीजन आपूर्ति को रोकने का काम कर रहे है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि कल पानीपत में हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारियों ने दिल्ली के हिस्से की ऑक्सीजन रोक ली जो रात 3 बजे तक भी नहीं भेजी जा सकी। उन्होंने बताया कि कल दिल्ली को 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में से केवल 177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल पाया क्योंकि हरियाणा और उत्तरप्रदेश के अधिकारियों द्वारा पुलिस की सहायता से दिल्ली के ऑक्सीजन टैंकरों को रोक दिया गया।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब है कि कुछ अस्पतालों में अगले 2-3 घंटे के लिए ही ऑक्सीजन उपलब्ध है और ज़्यादातर अस्पतालों में सिर्फ 7-8 घंटे के लिए ऑक्सीजन बाकी है। उपमुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि जिस दरियादिली से केंद्र सरकार ने कल दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया है। केंद्र सरकार अब कड़े कदम उठाते हुए उसकी आपूर्ति भी सुनिश्चित करें क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संकट के समय राज्यों को आपस में लड़ने के बजाय साथ मिलकर इस महामारी से लड़ना है इसलिए ऑक्सीजन को लेकर इस खींचतान को खत्म किया जाए।

अशोक वालिया का कोरोना से निधन

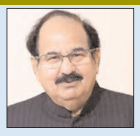

नई दिल्ली। दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक वालिया का कोरोना से संक्रमित होने के कारण गुरुवार को निधन हो गया। प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि डॉ वालिया कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उसके बाद उन्हें यहां अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां आज सुबह उनका निधन हो गया। डॉक्टर वालिया दिल्ली सरकार में लगातार 15 साल तक मंत्री रहे और तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के अत्यंत विश्वासपात्र थे। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। पेशे से चिकित्सक डॉ वालिया चार बार दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने वर्ष 1993 में राजनीति मे प्रवेश किया और दिल्ली सरकार में शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय जैसे अहम पदों पर काम किया।

नए मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे कई अस्पताल

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बाद कई अस्पतालों ने कोरोना पीड़ित नए मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया है। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में कुछ ही समय का ऑक्सीजन का स्टॉक बचा है। ऐसे में आईसीयू में बची हुई ऑक्सीजन इस्तेमाल करने और वार्डों में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अस्पताल ने नए कोरोना मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया है। इसी तरह रोहिणी स्थित बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में भी ऑक्सीजन की किल्लत के बाद नए मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया गया है। इसी तरह अपोलो, मैक्स, विमहंस जैसे अस्पतालों में भी कुछ समय के लिए नए मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है।

भाजपा ने केजरीवाल सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में अंतर : अनिल बाजपेयी

नई दिल्ली,(एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल बाजपेयी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथनी और करनी में काफी अंतर है। कैमरे के सामने लोगों की मदद करने के बड़े-बड़े वादे करने का ढोंग रचना और फिर दिल्लीवालों को उनकी हालत पर ही छोड़ देना, यह केजरीवाल अच्छी तरह से जानते हैं और पिछले 6 सालों से यही करते आ रहे हैं। अनिल बाजपेयी ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली के लोगों की मदद करने का बड़ा-बड़ा वादा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि प्रदेश के सरकारी तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बेड उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने सरकारी हॉस्पिटल में आईएएस नोडल अफसर लगा दिए हैं और उनकी हालत ये है कि उनको कई बार फोन करते हैं तो अधिकतर अधिकारियों के मोबाइल पर या तो घंटी बजती है या मोबाइल स्विच ऑफ होता है। अनिल बाजपेयी ने कहा कि दिल्ली के शांति मुकुंद हॉस्पिटल के चीफ एग्जक्युटिव अफसर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑफिस में कई बार फोन करके गुहार लगाई कि हॉस्पिटल में गैस खत्म हो रही है, कृपया इंतजाम कराए क्योंकि कई सारे मरीज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है। श्री बाजपेयी ने कहा कि केजरीवाल जी द्वारा ट्वीटर पर सभी को भारतीय बनकर कोरोना की इस लड़ाई में एक साथ लड़ने का संदेश बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर दिल्ली की जनता उनसे ऑक्सिजन के लिए गुहार लगाए और उसका इंतजाम न हो, तो ये बहुत दु:ख की बात है, उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुखिया से अनुरोध किया कि कृपया तुरंत शांति मुकंद हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए ताकि मौत और जिंदगी से लड़ रहे लोगों की जान बचाई जा सके।

संक्षिप्त खबर

बाल गृहों से मांगा कोरोना संक्रमित बच्चों का आंकड़ा

नई दिल्ली। देश के कई बाल संरक्षण गृहों में बच्चों के कोरोना वायरस की चपेट में आने की खबरों के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने राज्यों से इन गृहों में रहने वाले संक्रमित बच्चों का आंकड़ा मांगा है। आयोग ने सभी राज्यों से कहा है कि वे अपने यहां के इन गृहों में एक महीने के दौरान कोरोना से संक्रमित होने वाले बच्चों का आंकड़ा दें। प्रदेशों के प्रमुख सचिवों को लिखे पत्र में एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि कोरोना महामारी में बाल गृहों में रहने वाले बच्चों का संरक्षण मुख्य चिंता का विषय रहा है। आयोग ने कहा कि खबरों के मुताबिक, बाल गृहों में रहने वाले बच्चे कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं।

58 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों की फील्ड में नहीं होगी तैनाती

नई दिल्ली। कोरोना संकट को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त ने जवानों की कोरोना से सुरक्षा और बचाव के लिए बड़ा फैसला लिया है। पुलिस आयुक्त ने 58 साल से ज्यादा उम्र के पुलिसकर्मियों की तैनाती फील्ड में नहीं करने को कहा है, क्योंकि पिछले दिनों पीसीआर वैन में तैनात कई जवानों को कोरोना संक्रमण हुआ था। यहां संख्या लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया और अगले आदेश तक इसे जारी रखने के लिए कहा गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस के जवानों में लगातार कोरोना से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए मामलों में सामने आया कि संक्रमित हुए ज्यादात्तर जवानों की तैनाती पीसीआर वैन में की गई थी। वैन में भी ज्यादात्तर स्टाफ 50 साल से ऊपर की उम्र का था। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों ने फैसला लिया है कि अब पीसीआर वैन और फील्ड के अन्य कामों में 58 साल से कम उम्र के लोगों को लगाया जाएगा।

मरीजों ने रोजाना एंबुलेंस के लिए करीब 2500 कॉल किए

नई दिल्ली। दिल्ली में गत एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों ने एंबुलेंस के लिए रोजाना करीब 2,500 कॉल किए। दिल्ली सरकार द्वारा संकलित इन आंकड़ों से राजधानी में महामारी की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, गत एक हफ्ते में कुल 17,924 कॉल एंबुलेंस के लिए किए गए जिनमें निजी एंबुलेंस के लिए मरीजों द्वारा किए गए कॉल शामिल नहीं हैं। आंकड़ों के मुताबिक, गत एक हफ्ते से रोजाना कम से कम 2,560 कॉल एंबुलेंस के लिए आ रहे हैं।

दक्षिणी निगम की सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली,(एजेंसी)। दक्षिणी निगम ने गुरुवार को चारों जोन में सख्त कार्रवाई करते हुए कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन न करने पर 130 चालान किए। शारीरिक दूरी का पालन न करने और बिना मास्क बाहर घूमने वालों के चालान किए जा रहे है। निगम अधिकारियों द्वारा विभिन्न माध्यमों से नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है लेकिन अब भी नागरिक लापरवाही बरत रहे हैं जिस कारण सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी निगम द्वारा चारों ज़ोन में व्यापक स्तर पर सेनेटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है।मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थलों, कंटेन्मेंट जोन, क्वॉरंटीन सेंटर, वैक्सिनेशन केंद्र, अस्पतालों में 15 टैंकरों और 10 जेटिंग मशीन द्वारा सेनेटाइज़ेशन कार्य किया जा रहा है।चारों ज़ोन में आज लाजपत नगर, राजौरी गार्डन, पंजाबी बाग मार्केट, पालम, साकेत, संगम विहार, पुष्प विहार, मदनगीर, तिलक नगर, डिफेंस कॉलोनी में बड़े स्तर पर सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का छिड़काव किया गया। इसके अलावा कोरोना संक्रमित मरीजों के घरों से लगभग 100 किलो बायो मेडिकल वेस्ट उठाया गया।

कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का पालन न करने पर किए 130 चालान

डेंगू, मलेरिया एवं चिकुनगुनिया की रोकथाम के लिए बैठक आयोजित

नई दिल्ली,(एजेंसी)। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के कार्यालय में गुरुवार को ऑनलाइन माध्यम से अर्न्तविभागीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूर्वी दिल्ली के उप- महापौर, हरि प्रकाश बहादुर, स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष, कंचन माहेश्वरी और शाहदरा उत्तरी के वार्ड समिति अध्यक्ष, के के अग्रवाल, उप स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ. अजय हांडा और उप स्वास्थ्य अधिकारी, शाहदरा उत्तरी और बैठक की आयोजक, डॉ माधुरी पंत ने भाग लिया।

इस बैठक का उद्देश्य पूर्वी दिल्ली नगर निगम में मच्छर जनित बीमारियों के रोकथाम एवं उपचार हेतु विभिन्न विभागों की भागीदारी को सुनिश्चित करना था। शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के उपायुक्त, आर मेनका ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों ने ऑनलाईन भाग लिया। बैठक में आईटीआई नन्द नगरी, दिल्ली अग्नि शमन सेवाएं, दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन, दिल्ली जल बोर्ड, बीएसईएस, डीटीसी, एसडीएन अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, जेपीसी अस्पताल और इबहास आदि विभागों के नोडल अधिकारियों ने ऑनलाईन भाग लिया। उपायुक्त, आर मेनका ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिये कि किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान में मच्छर जनित परिस्थितियां पाये जाने पर समय रहते नियंत्रित किया जाये और सभी विभागों से मच्छर के लार्वा को प्रथम चरण में ही नियंत्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा डी.बी.सी एवं फील्ड वर्करों द्वारा इन ब्रिड़िंग साइट की निरंतर जांच तो की ही जा रही हैं लेकिन इस बात की आवश्यकता है कि प्रत्येक विभाग, भवन, वर्कशॉप अपना नोडल अधिकारी तय करे जो संबधित क्षेत्र में मच्छरों की रोकथाम संबंधी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हो। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी अपनी दैनिक रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को देगा। उन्होंने अर्न्तविभागीय समन्वय समिति की बैठक की उपयोगिता के संबंध में कहा कि पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए स्वास्थ्य जनक परिस्थितियों का निर्माण करना केवल नगर निगम का ही नहीं बल्कि अन्य विभागों का दायित्व भी है।

बैठक में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों ने लिया भाग

ड्रोन से होगी कोविड-19 के टीके की आपूर्ति

नई दिल्ली,(एजेंसी)। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ड्रोन से कोविड-19 के टीके की आपूर्ति की योजना बना रहा है और उसे अध्ययन के लिए ऐसा करने की सरकार से सशर्त मंजूरी मिल गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आईसीएमआर के आवेदन पर आज इसकी अनुमति दी। आईसीएमआर ने 22 फरवरी को मंत्रालय को ई-मेल कर ड्रोन से कोविड-19 टीके की आपूर्ति की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए अनुमति मांगी थी। यह फिजिबिलिटी स्टडी आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर की जा रही है।

मंत्रालय ने कहा है कि आवेदक को अध्ययन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की मंजूरी लेनी होगी। फिलहाल एक साल के लिए अनुमति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि देश में किसी भी पेलोड की डिलीवरी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन विशेष परिस्थिति को देखते हुए आईसीएमआर को इस नियम से छूट दी गई है।

होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के घरों को सैनिटाइज कर रहा निगम

(एजेंसी)

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के घरों को सैनिटाइज करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम विभिन्न क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाकर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कार्य कर रही हैं। महापौर जय प्रकाश ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा हेतु कोविड हेल्पलाइन नंबर 1800-200-8701 शुरू की हुई है। उन्होंने बताया कि इस कोविड हेल्पलाइन नंबर पर नागरिक आइसोलेशन सेंटर, बायो मेडिकल वेस्ट उठाने के संबंध में, कोविड टेस्टिंग सेंटर, कोविड टीकाकरण केंद्र, कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, श्मशान घाट व कब्रिस्तान और सैनिटाइजेशन के बारे में जानकारी व शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। महापौर श्री जय प्रकाश ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम करोना संक्रमण के मद्देनजर सभी आवश्यक कदम उठा रही है। महापौर जय प्रकाश ने नागरिकों से मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करने व बार बार हाथ धोने और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम कुछ सावधानियों से कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोक सकते हैं।

दि प्रिंट हिन्दी की संपादक रेणु अगल नहीं रहीं

नई दिल्ली,(एजेंसी)। राजधानी में एक सड़क दुर्घटना में घायल जानी-मानी पत्रकार और दि प्रिंट हिन्दी की संपादक रेणु अगल का कल देर रात उपचार के दौरान अस्पताल में निधन हो गया। सुश्री अगल इस माह के शुरू में एक दुर्घटना का शिकार हो गईं थीं और उनके सिर में गंभीर चोटें आयीं थीं जिसके बाद से वह दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थीं। उनके निधन से पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गयी। भारतीय प्रेस क्लब, महिला प्रेस क्लब, विभिन्न पत्रकार संगठनों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज से स्नातक करने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) से पढ़ीं सुश्री अगल समाचार एजेंसी यूनीवार्ता और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में काम करने के बाद 1996 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (बीबीसी) की हिन्दी सेवा में बतौर प्रोड्यूसर शामिल हुईं और जल्द ही उन्होंने एक प्रभावशाली पहचान स्थापित कर ली। बीबीसी के बाद उन्होंने पेंग्विन इंडिया और जगरनॉट प्रकाशन समूहों में हिन्दी की संपादक के रूप में काम किया।

कड़कड़डूमा शमशान घाट में सीएनजी आधारित शवदाह गृह की शुरुआत

(एजेंसी)

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन ने गुरुवार को कड़कड़डूमा शमशान घाट में सीएनजी प्रणाली द्वारा निर्मित शवदाहगृह का उदघाटन किया गया।

इस मौके पर नेता सदन प्रवेश शर्मा, स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षा, कंचन महेशवरी , स्थानीय निगम पार्षद बबीता खन्ना तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इस मौके पर बोलते हुए निर्मल जैन ने बताया कि कोरोना की महामारी के कारण मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में शमशान घाटों में जगह की कमी महसूस की जा रही है इसके अतिरिक्त ज्यादा अंत्येष्टि के कारण लकड़ियों की भी कमी हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस कार्य को पिछले कई सप्ताह से निगम के विभिन्न विभागों के द्वारा दिन-रात कार्य करके पूर्ण किया गया है। महापौर ने जानकारी देते हुए बताया कि संपीड़ित प्रकृतिक गैस निर्मित शव दाह में शरीर का दाह संस्कार लगभग 45 मिनट में पूरा हो जाता है और परिजन अस्थियों को लगभग 1:30 घंटे के बाद ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा संपीड़ित प्रकृतिक गैस प्रणाली से दाह संस्कार करने हेतू शुल्क मात्र 1500 प्रतिदाह तय किया गया है लेकिन कोरोना निर्धारित अस्पतालों में हुई मृत्यु का दाह संस्कार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस मौके पर बोलते हुए प्रवेश शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में निगम द्वारा संपीड़ित प्रकृतिक गैस निर्मित शवदाह गृह को शुरू करना अपने आप में एक उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में निगम आयुक्त श्री विकास आनंद का बहुत सहयोग मिला है जिन्होंने निर्धारित समय से पहले ही इसे तैयार करवा दिया।

संयुक्त किसान मोर्चा और राकेश टिकैत की छवि लगातार हो रही खराब, आखिर कब समझेंगे जनता का मिजाज

नई दिल्ली/सोनीपत/गाजियाबाद । एक ओर जहां दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना लाखों मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दिल्ली-एनसीआर के बॉर्डर पर बैठे किसान प्रदर्शनकारी महामारी के खिलाफ जंग में अड़ंगा लगाने में जुटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी न तो कोरोना की जांच करवा रहे हैं और न ही कोरोना का टीका लगवाने को तैयार है। इस बीच अब तो महामारी के दौर में सिंघु, टीकरी व गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारी ऑक्सीजन टैंकरों के रास्ते में बाधा डाल रहे हैं, जिसके चलते कोरोना मरीजों की जान को भी खतरा उत्पन्न होने लगा है।

रास्ता बंद होने से दिल्ली समेत कई राज्यों के अस्पतालों तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचने में देरी हो रही है। प्रदर्शनकारियों के रास्ता रोककर बैठे होने की वजह से ऑक्सीजन टैंकर या तो गांव की संकरी गलियों में फंस कर खड़े हो जा रहे हैं या फिर उन्हें कई किलोमीटर दूर तक घूमकर अस्पताल तक जाना पड़ रहा है। इसका नतीजा कोरोना मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।

वहीं, इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर पर रास्ता बाधित होने से ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा आ रही है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को मानवता के नाते ऑक्सीजन के टैंकर को रास्ता देना चाहिए। इस समय दिल्ली के लोगों की जान बचाना जरूरी है ना कि आंदोलन। इसलिए आंदोलन स्थगित कर ऑक्सीजन के टैंकर को रास्ता देना चाहिए।

दरअसल, बुधवार को हरियाणा से दिल्ली आ रहे ऑक्सीजन टैंकर को प्रदर्शनकारियों के हाईवे पर बैठे होने से हरियाणा के कुंडली गांव की संकरी गलियों के रास्ते से आना पड़ा। ये रास्ते इतने बड़े टैंकरों का दबाव सहने लायक नहीं हैं। नतीजतन टैंकर 45 मिनट तक गांव में ही फंसा खड़ा रहा। बाद में दिल्ली व हरियाणा पुलिस ने मिलकर टैंकर को बाहर निकलवाया। टैंकर के समय पर अस्पताल न पहुंचने की वजह से अस्पताल में दाखिल सैकड़ों कोरोना संक्रमितों की जान दाव पर लग गई थी। अगर पुलिस टैंकर को न निकालती तो बड़ी घटना घट सकती थी। उधर, प्रदर्शनकारी उल्टा पुलिस पर रास्ता बंद करने के आरोप लगा रहे हैं।

कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज के कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन खत्म, यहां 100 मरीज हैं भर्ती

नई दिल्ली । कोरोना के मामलों में तेजी से हो रहे इजाफे के बीच दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बनाये गए कोविड केयर सेन्टर में ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है. इस कोविड केयर सेन्टर में सभी ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हुए. यहां पर करीब 100 कोरोना मरीज एडमिट हैं. चूंकि यह एक अस्थाई इंतजाम है इसलिए यहां मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर/ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन देने का काम होता है. फिलहाल किसी तरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बदल-बदल कर बारी-बारी से मरीजों को ऑक्सीजन देने का काम चल रहा है. दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में सोमवार से शुरू हुआ है, ये कोविड केयर सेन्टर मुख्य रूप से ऑक्सीजन युक्त बेड के चलते ही चर्चा में था.

गौरतलब है कि देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं दबाव में हैं और ज्यादातर शहरों में अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है. ऑक्सीजन की किल्लत किसी से छुपी नहीं है. ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार से सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी एक आदेश जारी किया है कि कहीं भी ऑक्सीजन को रोका नहीं जाएगा. केंद्र का आदेश यह सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को भेजा गया है.

इस बीच, कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई और उसकी उपलब्धता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में ऑक्सीजन सप्लाई की उपलब्धता बढ़ाने के तरीकों और साधने पर चर्चा की गई. इस मौके पर अधिकारियों ने पीएम को पिछले कुछ सप्ताहों में ऑक्सीजन की सप्लाई में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी. पीएम ने इस दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, ऑक्सीजन आपूर्ति की गति में तेजी लाने और इनावेटिक तरीकों से हेल्थ फेसिलिटी को ऑक्सीजन सपोर्ट मुहैया कराने जैसे पहलुओं पर तत्परता से काम करने की जरूरत बताई.

कोरोना टेस्ट करवाने से घबरा रहे प्रदर्शनकारी, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य मंजीत राय को सरकार पर शक

नई दिल्ली/सोनीपत । दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण अपना कहर बरपा रहा है। तेजी से बढ़ रहे कोरोनों के मामलों के बीच जहां देश में 24 घंटे में 2000 लोगों की जान जा रही है तो दिल्ली 200 से ज्यादा लोग जान गंवाने लगे हैं। इस बीज दिल्ली-एनसीआर के बॉर्डर पर बैठे किसान इस विपरीत हालात में आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार नहीं हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के सुर ही अलग-अलग हैं। कोई कहता है कि कोरोना का टीका लगवाएं तो कोई इससे इनकार ही कर रहा है। ताजा मामले में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य मंजीत राय ने कोरोना की जांच नहीं करवाने के पीछे यह तर्क दिया है कि कहां सरकार जांच के नाम थोखा न कर दे।

कोरोना की जांच नहीं कराएंगे आंदोलनकारी - संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य मंजीत राय का कहना है कि पिछले दिनों सोनीपत जिला प्रशासन के साथ उनकी एक बैठक भी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार की ओर से कोरोना संबंधी किसी प्रकार की जांच में वे शामिल नहीं होंगे क्योंकि अगर उनको जांच की जरूरत है तो वो जांच वे खुद करवाएंगे।

किसान नेता मंजीत राय का कहना है कि हरियाणा सरकार जांच के नाम पर उनके साथ भी धोखा कर सकती है। नेताओं को लग रहा है कि जांच के नाम पर हरियाणा सरकार बल प्रयोग कर उन्हें यहां से हटा सकती है और पिछले साढ़े चार महीने से चला रहा किसान आंदोलन खत्म करवा सकती है।

वहीं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ताजा बयान में कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान टीका जरूर लगवाएंगे। कुछ किसानों का कहना है कि वे अपने गृहराज्य में ही कोरोना का टीका लगवा कर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। वह बीच में जाकर कोरोना के टीके की दूसरी डोज भी लगवाकर आ जाएंगे।

संपादकीय

निजी कंपनियों की बड़ी जिम्मेदारी

भारत को आने वाले दिनों में एक बड़ा काम करना है। उसे अपनी अर्थव्यवस्था 'फिर से बेहतर' बनानी है, जो कोविड महामारी के पहले भी अच्छी तरह काम नहीं कर रही थी। देश में न तो पर्याप्त रोजगार पैदा हो रहे थे, और न कामगारों व किसानों की आमदनी बढ़ रही थी। लोगों को भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही थीं। बेशक, सरकार के हाथ तंग हैं, पर उसे ऐसे रास्ते खोजने होंगे कि सार्वजनिक सेवाओं के लिए पैसों की कमी न होने पाए। पूंजी जुटाने के लिए ही सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) का निजीकरण किया जा रहा है, और ऐसी निजी कंपनियां खोजी जा रही हैं, जो इनको अधिक कुशलता से चला सकें।

पिछले महीने अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने यह कहा कि ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक व शासकीय) संकेतकों के मुताबिक तमाम सूचीबद्ध कंपनियों को अब अपने सर्वांगीण प्रदर्शन की जानकारी साझा करनी होगी, यानी यह बताना होगा कि पर्यावरण और सामाजिक हालात पर उनके कारोबार का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सिर्फ आर्थिक लेखा-जोखा (राजस्व-वृद्धि, लाभ व शेयरधारक मूल्य) से वे अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकतीं। सभी उद्यमों को इस मामले में पारदर्शी होना ही चाहिए कि वे समाज के लिए क्या कर रहे हैं? एसईसी समझ गया है कि कंपनियों के व्यापक सार्वजनिक उद्देश्यों को आधिकारिक जामा पहनाने का वक्त आ गया है। 'कुल शेयर धारक रिटर्न' अब कंपनी की सेहत का अच्छा मापक नहीं है, और न ही सकल घरेलू उत्पाद' (जीडीपी)अर्थव्यवस्था का।

अगर इस महामारी ने वैश्विक समस्याएं हल करने वालों को कोई सबक सिखाया है, तो वह यह कि लॉकडाउन और वैक्सीन जैसे सख्त उपायों के दुष्प्रभावों से सावधान रहने की जरूरत है। ये समस्या का जितना समाधान नहीं करते, उससे अधिक तंत्र की सेहत बिगाड़ देते हैं। इसीलिए, केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के लिए वैसी दवा न ढूंढ़े, जिसके दुष्प्रभाव हमें पहले से पता हैं। भले ही, निजीकरण से सरकार को जरूरी पैसे मिल सकते हैं, पर इसकी रूपरेखा और सीमा को दुरुस्त किए बिना ऐसा करना अर्थव्यवस्था व समाज को कई रूपों में नुकसान पहुंचाएगा। निजीकरण दवा का ऐसा 'हाई डोज' है, जिसका इस्तेमाल मार्गरेट थैचर ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए किया था, पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को इससे बाहर रखा गया था। निजी स्वास्थ्य सेवा जैसी दवा की लत तो अमेरिका को है, जिसकी गड़बड़ियां लंबे समय से जगजाहिर हैं और कोविड महामारी के दौरान यह कहीं अधिक गहरी होती दिखीं। अपने यहां कई सार्वजनिक उपक्रमों की सेहत ठीक करनी होगी, और निजी उद्यमों की सार्वजनिक जवाबदेही में सुधार लाना होगा। इसके लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाना आवश्यक है। मसलन, उद्यम ऐसे होने चाहिए, जो अपने तमाम संसाधनों का कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करें और सार्वजनिक जरूरतों के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन भी करें। इसकी रूपरेखा बनाई भी गई है। करीब 10 साल पहले जिम्मेदार उद्यमियों ने भारतीय कंपनियों के लिए 'नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइन्स' (स्वैच्छिक राष्ट्रीय कार्ययोजना) बनाई थी। लगभग उसी समय, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सार्वजनिक उद्यमों के प्रशासनिक कामकाज में सुधार के लिए 'एगेनफिकेशन' (सरकारी दखलंदाजी से मुक्त अर्द्ध-सरकारी संस्था) की सिफारिश की थी। वित्तीय और सामाजिक क्षेत्रों से भी 'सामाजिक उद्यमों' की नई अवधारणाएं उभर रही हैं। ऐसे में, हमें सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने से पहले इन नई अवधारणाओं पर गौर करना चाहिए। सार्वजनिक उद्देश्यों को पूरा करने वाली पेशेवर कंपनियां तीन स्तंभों पर टिकी होनी चाहिए। पहला, उद्देश्यों में पारदर्शिता। उद्यम चाहे सरकारी हों या निजी, उनका एकमात्र मकसद लाभ कमाना और निवेशकों की संपत्ति को बढ़ाना नहीं हो सकता। लक्ष्य व उसकी रूपरेखा साफ-साफ परिभाषित होनी चाहिए और कंपनियों व उनके कर्ता-धर्ताओं के प्रदर्शन को परखने का अधिकार जनता को मिलना चाहिए।

दूसरा, कंपनी के प्रबंधकों को इतनी आजादी होनी चाहिए कि लक्ष्य को पाने का वे सर्वोत्तम रास्ता खोज सकें। इसमें नौकरशाहों का दखल न हो। हां, एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा इनकी निगरानी की जा सकती है। और तीसरा स्तंभ है, सामाजिक मूल्यों के मुताबिक उन सीमाओं का निर्धारण करना, जिनके भीतर बोर्ड अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सके। आर्थिक फैसलों व मानव संसाधन के प्रबंधन के लिए भी व्यापक दिशा-निर्देश जरूरी हैं। निजी कंपनियों को अपने आर्थिक फैसले समझदारी से लेने होंगे। हालांकि, आर्थिक उदारीकरण के कारण एग्जीक्यूटिव पे पर नियंत्रण किया जाता रहा है। इसने पिछले 30 वर्षों में निजी कंपनियों के सीईओ व कामगारों की आय की खाई दस गुना से अधिक बढ़ा दी है। बेशक, शीर्ष अधिकारियों के पास ज्यादा जिम्मेदारी होती है और किसी कंपनी के समग्र प्रदर्शन में वे कहीं ज्यादा योगदान दे सकते हैं। मगर यह समझ से परे है कि पिछले तीन दशकों में उन्होंने भला कैसे कंपनी के हित में दस गुना अधिक मूल्य जोड़ना शुरू किया है। वित्तीय नियंत्रकों द्वारा संचालित कंपनियां बहुत दिनों तक काम की नहीं रहतीं, हालांकि उनसे अल्पकालिक फायदा हो सकता है। इन दिनों देश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः केंद्रीय बैंकों और वित्त मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें धन व वित्त का प्रबंधन आर्थिक सिद्धांतों के मुताबिक होता है। वित्तीय प्रबंधन से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपनियों व देशों के प्रबंधकों का यही अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सभी निजी कंपनियां अपने लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करती हैं, जबकि उनको इसके लिए जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता। जैसे, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का उल्लेखनीय आर्थिक प्रदर्शन सरकार द्वारा वित्त-पोषित शैक्षणिक संस्थानों के कारण हुआ था, जहां से उन्हें उच्च गुणवत्ता के संसाधन बहुत कम लागत में मिल गए थे। लिहाजा हमें इन नैतिक सवालों का जवाब ढूंढ़ना ही होगा कि 21वीं सदी में खरे उतरने वाले उद्यमों की रूपरेखा क्या हो? किसके लिए हमारे कथित पूंजी-निर्माता धन पैदा करते हैं? इस पूंजी को बनाने में वे किन संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं? और इसका कितना हिस्सा वे समाज को लौटाते हैं , और कितना हमारी अर्थव्यवस्था के कैशियर होने के नाते वे अपने पास रखते हैं?

प्रवीण कुमार सिंह

घाव भरने का कारगर उपाय: सभी मजहबी संप्रदायों को एक मंच पर लाकर संवाद कराने की जरूरत

> दुनिया के 40 देशों में टीआरसी है। टीआरसी भिन्न-भिन्न आग्रही समूहों को एक मंच पर लाने वाली संस्था है। भारत में सैकड़ों वर्षों से मजहबी सांप्रदायिक तनाव हैं। मूलभूत प्रश्न है कि क्या भारत में भी टीआरसी की आवश्यकता है? हिंदू प्रतीक्षा में हैं कि उनकी व्यथा सुनी जानी चाहिए। अन्य संप्रदायों को भी अलगाववाद की उनकी निष्ठा आदि विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। सबको एक मंच पर लाकर संवाद कराने की जरूरत है। यह टीआरसी जैसी संस्था से संभव है। भारत में टीआरसी को समन के अधिकार सहित कुछ अन्य अधिकार दिए जा सकते हैं।

गहरे घाव जल्दी नहीं भरते। राष्ट्र जीवन पर हुए आक्रमणों के घाव लगातार व्यथित करते हैं। भारत के मन पर भी गहरे घाव हैं। राष्ट्रीय स्मृति उन्हें कुरेदती रहती है। राष्ट्र घनीभूत पीड़ा झेलता है। भारतीय संस्कृति और राष्ट्र पर हुए हमलों का इतिहास पुराना है। कुछ विद्वान इस विवरण को स्वाधीनता संग्राम व स्वाधीनता के समय से प्रारंभ करते हैं और कुछ सन् 711 के मो. बिन कासिम के हमले से। भारत ब्रिटिश सत्ता से 1947 में स्वतंत्र हुआ। इसी समय भारत विभाजन हुआ। यह भयंकर रक्तपात से भरापूरा था। लाखों लोगों के घर-परिवार छूटे। कांग्रेस व मुस्लिम लीग को सत्ता मिली। दोनों ने अपने-अपने सत्ता क्षेत्रों में पीड़ितों की चिंता नहीं की। पाकिस्तानी राज्य में हिंदू उत्पीड़न जारी है। भारत में इतिहास का विरूपण हुआ। इस्लामिक हमलावरों की भी पक्षधरता हुई। इस्लामी राजनीति औरंगजेब, गोरी, गजनी को अपना नायक बताती है। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने मध्यकालीन इस्लामी आक्रामकता का कार्यकाल 762 वर्ष बताया है।

इस्लामी आक्रांताओं ने भारत को लूटा था। लाखों मंदिर गिराए गए थे। लाखों हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ। मंदिर ध्वस्तीकरण व धर्मांतरण इस्लामी सत्ता में भी जारी था। स्वतंत्र भारत में आज भी धन लोभ व जबर्दस्ती के धर्मांतरण हैं। भारत पर पहला हमला सन् 711 में मो. बिन कासिम ने उत्तर पश्चिम से किया था। गजनी के महमूद ने सन् 1001 में लगातार 17 भयावह हमले किए। सिमी जैसे संगठनों ने स्वतंत्र भारत में गजनी को महानायक बताया और अल्लाह से गुजारिश की-'या इलाही भेज दे, महमूद कोई।' 1173 में मोहम्मद गोरी ने इसी तरह हमला किया। इसके बाद 1221 में चंगेज खां, फिर 1398 में तैमूर ने भयानक हमले किए। 1526 में बाबर चढ़ आया। 1738 में नादिर शाह और

1761 में अब्दाली का हमला।

डॉ. आंबेडकर ने लिखा है कि 'इन हमलों का उद्देश्य लूट करना ही नहीं था। इनका उद्देश्य मूर्ति मंदिर का ध्वस्तीकरण व भारत का इस्लामीकरण था।' उन्होंने मो. बिन कासिम द्वारा हज्जाज को लिखे खत का उल्लेख किया है, 'मूर्ति पूजकों का इस्लामी धर्मांतरण करा दिया गया है। मूर्तियों मंदिरों की जगह मस्जिदें बना दी गई हैं।' इसी तर्ज पर अयोध्या, मथुरा और काशी सहित भारत के लाखों मंदिरों का ध्वस्तीकरण किया गया। भारत में राष्ट्रीय एकता की प्रमुख समस्या मजहबी सांप्रदायिकता है। नागरिकता संशोधन कानून का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है बावजूद इसके उक्त कानून के विरोध में जबर्दस्त आंदोलन हुए। वे राष्ट्रभाव के विरोध में आक्रामक रहते हैं। वे लड़कियों का जोर जबर्दस्ती धर्मांतरण कराते हैं। विवाह कराते हैं। ईसाई मिशनरी भी धर्मांतरण में पीछे नहीं हैं। हिंदू सैकड़ों वर्ष से अपमानित हैं। ऐसे सांप्रदायिक तत्वों के मन में मजहबी श्रेष्ठता की ग्रंथि है। ब्रिटिश राज के समर्थक ईसाई मिशनरियों के मन में भी ऐसा ही भाव है। दोनों यहां शासक रहे हैं। लेकिन हिंदू बहुसंख्यक हैं। इसके बावजूद अपने ऊपर हुए अत्याचारों के विरुद्ध सक्रिय नहीं होते। वे संविधान और संस्कृति के प्रति एकनिष्ठ हैं। सो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए सभी पक्षों व आस्था समूहों के मध्य तनाव नहीं अंतरसंगीत चाहिए। मूलभूत प्रश्न है कि भारत के सभी वर्ग समूह एक साथ प्रसन्न मन क्यों नहीं रह सकते? हम सब मिलकर संवादहीनता की यह स्थिति क्यों नहीं दूर कर सकते? सत्य तथ्य भी होता है। हिंदू व्यथा सत्य है। यही तथ्य इतिहास भी है। इतिहास कल्पना नहीं होता, लेकिन सरकारों ने इतिहास को मनमाने ढंग से लिखवाया।

लंदन विश्वविद्यालय के रीडर एएल बाशम ने 'दि वंडर दैट वाज इंडिया' लिखी थी। किताब के प्रारंभ में उल्लेख है, 'मुसलमानों के भारत आने के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति का सर्वेक्षण।' उनके शब्द ध्यान देने योग्य हैं। वे लिखते हैं, 'भारत हर्षोल्लास पूर्ण देश था। यहां के निवासियों ने शनैः शनैः विकसित सामाजिक प्रणाली में पारस्परिक संबंधों के सहारे दयालुता व सौजन्य के उस स्तर को प्राप्त किया, जो किसी भी जाति (राष्ट्रीयता) के स्तर से अपेक्षाकृत उच्च था।' उनकी बातें सत्य हैं। सबके तथ्य अपने होते हैं और सत्य भी, लेकिन राष्ट्रीय सत्य सर्वोपरि होता है। इसलिए भिन्न भिन्न सत्य आग्रहियों के मध्य संवाद और सुलह जरूरी है।

इसका सुंदर प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। नेल्सन मंडेला के सत्तारूढ़ होने के पहले का श्वेत शासन अत्याचारी था। काले-गोरे का भेद था। काले लोगों का भयंकर उत्पीड़न हुआ था। मानवीय गरिमा भी कुचली गई थी। देश को स्वतंत्रता मिली। मंडेला सत्ता में आए। राजनीतिक टिप्पणीकारों का अनुमान था कि अब यहां नरसंहार की संभावना है।

चुनौती बड़ी थी। मंडेला ने 'ट्रुथ एंड रिकांसीलिएशन कमीशन' (सत्य और समझौता/सुलह आयोग-टीआरसी) गठित किया। यह न्यायिक प्रकृति वाला आयोग था। पीड़ितों को खुलेआम अपनी व्यथा सुनाने का अवसर दिया गया। सभी पक्षों की सुनवाई में सत्य प्राप्ति का उद्देश्य था। परस्पर आत्मीयता का संवर्धन भी आयोग का लक्ष्य था। समाचार माध्यमों को खुली छूट थी। टीआरसी के इस महत्वपूर्ण कार्य पर फिल्म निर्माण, उपन्यास, काव्य रचना के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। श्वेत सरकार के अत्याचार का सत्य उद्घाटित था। सबके मध्य आत्मीयता का विकास मुख्य ध्येय था। इससे हिंसा बची। दक्षिण अफ्रीकी टीआरसी की प्रशंसा पूरे विश्व ने की।

राष्ट्रजीवन में वर्ग तनाव होते हैं। सामाजिक पहचान के भी तनाव होते हैं। अमेरिका में श्वेत-अश्वेत का तनाव है। वहां भी टीआरसी की चर्चा है। दुनिया के 40 देशों में टीआरसी है। टीआरसी भिन्न-भिन्न आग्रही समूहों को एक मंच पर लाने वाली संस्था है। भारत में सैकड़ों वर्षों से मजहबी सांप्रदायिक तनाव हैं। मूलभूत प्रश्न है कि क्या भारत में भी टीआरसी की आवश्यकता है? हिंदू प्रतीक्षा में हैं कि उनकी व्यथा सुनी जानी चाहिए। अन्य संप्रदायों को भी अलगाववाद की उनकी निष्ठा आदि विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। सबको एक मंच पर लाकर संवाद कराने की जरूरत है। यह टीआरसी जैसी संस्था से संभव है। भारत में टीआरसी को समन के अधिकार सहित कुछ अन्य अधिकार दिए जा सकते हैं। कुछ न कुछ करना ही होगा। घाव को खुला छोड़ना अच्छा नहीं होता।

अपने ही जाल में फंसे इमरान

अपनी गलत प्राथमिकताओं और समझौतापरस्त नीतियों के चलते पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ऐसी स्थिति में फंस गई है कि उससे न आगे बढ़ते बन रहा है और न पीछे हटते। एक सप्ताह पहले जिस तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) को आतंकी संगठन बताते हुए इमरान सरकार ने बैन किया था, उसी के आगे घुटने टेकते हुए उसने यह स्वीकार कर लिया है कि संसद की दो दिवसीय बैठक बुलाकर उसमें फ्रांसीसी राजदूत को वापस भेजने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ध्यान रहे, पाकिस्तान सरकार और खुद प्रधानमंत्री इमरान खान भी फ्रांसीसी राजदूत को वापस भेजे जाने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। पिछले दिनों उन्होंने टीवी पर प्रसारित एक संबोधन में कहा था कि फ्रांसीसी राजदूत को वापस भेजने का मतलब होगा पूरे यूरोपियन यूनियन (ईयू) से रिश्ते खत्म होना। चूंकि पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 50 फीसदी यूरोप को जाता है, इसलिए ईयू से रिश्ते खत्म होने का मतलब होगा देश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का आधा हिस्सा गायब हो जाना। मगर इमरान खान की ये समझदारी की बातें टीएलपी के जुनूनी समर्थकों को समझ में नहीं आनी थीं, ना आईं। उन्होंने अपना कथित आंदोलन तेज कर दिया और देश में जगह-जगह आंदोलनकारियों की पुलिस से मुठभेड़ शुरू हो गई। चार पुलिसकर्मी मारे गए और बड़ी संख्या में घायल हुए। यही नहीं करीब दर्जन भर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बंधक भी बना लिए गए।

नतीजा यह कि अपने ही देश में पाकिस्तान सरकार ऐसी लाचार हो गई कि उसे इस प्रतिबंधित आतंकी संगठन के साथ बातचीत करके बाकायदा समझौता करना पड़ा। इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अपने देश और सरकार को इस अपमानजनक स्थिति में पहुंचाने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वह हैं खुद प्रधानमंत्री इमरान खान। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने अगर मोहम्मद साहब के कार्टून छापने को अपने देश के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा मसला बताया था, तो यह उनके देश और संविधान के दायरे में आने वाली बात थी। अन्य देशों की तरह पाकिस्तान के भी धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों ने इस पर प्रतिक्रिया दी भी तो बतौर प्रधानमंत्री इमरान खान को उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए थी। मगर उन्होंने इसे इस्लामी जगत में अपना कद ऊंचा करने के एक मौके के रूप में देखा और भुनाने में जुट गए। इसी का परिणाम है कि देश के अंदर कट्टरपंथियों की हिम्मत और ताकत इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने सरकार को घुटने पर ला दिया। मामला भले पाकिस्तान का हो, सबक इसमें हर देश और समाज के लिए है। धार्मिक कट्टरपंथ को अगर आपने किसी भी रूप में बढ़ावा देना शुरू किया तो फिर यह सिलसिला आसानी से नहीं थमता। आखिरकार उसकी कीमत पूरे समाज को चुकानी पड़ती है।

रोबोटिक वेपनरी सिस्टम से नक्सलवाद को दिया जाए मुंहतोड़ जवाब

भारत में नक्सल संकट आतंक का रूप ले चुका है। इसलिए इसे अब गंभीरता से लेना होगा। लेकिन इनसे निपटें कैसें? बेशक हमारे सुरक्षाकर्मी बहादुर और बलिदानी हैं, पर इनसे निपटने में हमें रोबोटिक्स का सहारा लेना चाहिए। रोबोटिक वेपनरी सिस्टम ही इनसे निपटने का सही तरीका है। वही इनके साथ सटीक और मारक मुकाबला कर सकते हैं। दुनिया के कई देश अपने यहां आतंक से ऐसे ही निपट रहे हैं। आज दुनिया के 44 देशों के पास रोबोटिक वेपनरी सिस्टम है। इस मामले में हम रूस अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन, इजराइल हमकदम हैं। ढाई साल पहले हैदराबाद के एच बोटस रोबोटिक्स ने पांच फुट सात इंच के 43 किलो वजनी जिस स्मार्ट पुलिस रोबोट को लांच किया था, वह तो महज शिकायत दर्ज करने, संदिग्धों की निशानदेही, ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग और ऐसे कुछ सामान्य कार्य कर सकता था, लेकिन अब यह काफी विकसित हो चुका है। अब ऐसे रोबोट आसपास के परिवेश को भांपने, आधा दर्जन से ज्यादा भाषाएं बूझने वाले हैं। बस्तर में कई स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल और सुरक्षाकर्मियों का इससे परिचित न होना भी एक समस्या है। ये रोबोट कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एलईडी लाइट्स, सक्षम सेंसर, बढ़िया कैमरे और थर्मल इमेजिंग की सुविधा से लैस हैं। सर्विलांस, मैपिंग व डाटा एनॉलिसिस के लिए भी बेहतर हैं। यह दावा किया गया है कि सीधी मुठभेड़ों में इनका इस्तेमाल बेहद कारगर होने वाला है। दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती के लिए ये बहुत मुफीद होंगे। डीआरडीओ का दावा था कि चूंकि ये रोबोट राडार और सेंसर संपन्न हैं, सो रात की लड़ाई में सुरक्षा बलों से बेहतर साबित होंगे। पर किसी ऐसे ऑपरेशन में इनका यह कौशल आजमाया नहीं गया।

सबसे पहला ऐसा ह्यूमनाइड रोबोट दुबई में बना था, यह दूसरा है। मगर एक मामले में यह अव्वल है कि दुबई में बना ह्यूमनाइड रोबोट फ्रांस में तैयार किया गया था, जबकि अपना रोबोट पूरी तरह से भारतीय संसाधनों और वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित है। अपना रोबोट कुछ ज्यादा ही उन्नत है। सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञानी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यह पूर्णतया समायोजन रखता है। कुल मिलाकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कंप्यूटराइजेशन तथा रोबोटिक्स के मेल से अति उन्नत 'रोबोकॉप' हम आसानी से बना सकते हैं और सीमाओं, दुर्गम नक्सल क्षेत्रों तथा आतंक आशंकित इलाकों में तैनात कर सकते हैं। जंगलों, पहाड़ों या जहां नागरिक चपेट में न आते हों, वहां होने वाली मुठभेड़ों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या व्यवस्था इसके लिए तैयार होगी? शायद नहीं। भारत में भी यह तर्क दिया गया कि रोबोट के पास कभी इतनी बुद्धिमत्ता नहीं हो सकती कि वह युद्ध या मुठभेड़ के साथ जुड़े सामरिक और भू-राजनीतिक जोखिमों का अंदाजा लगा कर उसके हिसाब से निर्णय कर सके।

बेशक इस तरह के मशीनी सुरक्षाकर्मी की तैनाती के पीछे कई तरह की तकनीक और नैतिक सवाल हैं। मशीन को खुद फैसले लेने की ताकत देना कि वह अपने लक्ष्य खुद तय करे और उन्हें भेद सके, 'ऑटोनोमस' हो, इंसान की मदद या निर्देश की जरूरत न रहे तो मशीन बेलगाम हो जाएगी, तकनीक गलत फैसले ले सकती है, वह हमेशा कामयाबी के साथ सही लक्ष्य और बचाव में अंतर नहीं कर पाएगी। वह दुश्मनों के साथ बेकसूर नागरिकों को भी निशाना बना सकती है। परंतु मौजूदा वक्त में इस्तेमाल होने वाले स्वायत्त हथियारों का दायरा भी खासा बड़ा है। पैटिऑट मिसाइल से लेकर टर्मिनेटर तक। फिर इन्हीं पर रोक क्यों? हम इन्हें उन इलाकों में तो इस्तेमाल में ला ही सकते हैं जहां आबादी बहुत कम हो और आमजन के शिकार हो जाने की आशंका नहीं हो।

चार लाख से अधिक मंदिरों पर सरकारी?कब्जा, किंतु चर्च या मस्जिद पर नियंत्रण नहीं

> कई मंदिरों में ऑडिट फीस, प्रशासन चलाने की फीस और दूसरे तरह के टैक्स वसूले जाते हैं। किसी-किसी मंदिर की आय का लगभग 65-70 फीसद तक सरकार हथिया लेती है। 1986-2005 के बीच तमिलनाडु में मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन उनसे छिन गई। हजारों एकड़ पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है। यह सब सरकारी कब्जे की व्यवस्था का नमूना है। याद रहे कि भारतीय परंपरा में किसी हिंदू राजा ने मंदिरों पर अधिकार या नियंत्रण नहीं जताया, न उनसे कर वसूला। धार्मिक कार्यों में राजा द्वारा हस्तक्षेप के उदाहरण नहीं मिलते। वे तो सहायता ही देते थे। मुगल काल में मंदिरों को तरह-तरह के राजकीय अत्याचार झेलने पड़ते थे। दुर्भाग्यवश स्वतंत्र भारत में भी हिंदू समुदाय को अपने धार्मिक-शैक्षिक-सांस्कृतिक संस्थान चलाने का वह अधिकार नहीं, जो अन्य को है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की ओर से राज्य के 51 मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की घोषणा उस मुहिम का नतीजा है, जिसके तहत कुछ समय से सचेत हिंदू पूरे देश में मंदिरों की मुक्ति का अभियान चला रहे हैं। धीरे-धीरे इसमें इतनी गति आ गई है कि राजनीतिक दल भी इसे अपने वादों में स्थान देने लगे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने लोगों से निवेदन किया कि वे वोट मांगने वालों से मंदिरों को राजकीय चंगुल से मुक्त कराने का वचन लें। इसी तरह अपवर्ड, जयपुर डायलॉग्स जैसे कुछ शैक्षिक-वैचारिक मंच भी इसके लिए जन-जागरण चला रहे हैं। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई मंदिरों के लिए केंद्रीय बोर्ड बनाने की भी बात छेड़ी है यानी मंदिरों को अप्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव। इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं हुई हैं। इसके पीछे कुछ विशेष संगठनों को मंदिरों के संचालन में स्थायी अधिकार देने की योजना देखी जा रही है। यह आशंका निराधार नहीं।

हमारे देश में स्वतंत्रता के समय से ही सोवियत मॉडल पर राज्यतंत्र के अधिकाधिक विस्तार की बुरी परंपरा बनी। उससे होने वाली हानियां, व्यापक भ्रष्टाचार और अंततः सोवियत संघ का विघटन देखकर भी हमारे राजनीतिक दलों में उसका आकर्षण नहीं घटा। कारण यही है कि राज्यतंत्र का विस्तार उनकी निजी ताकत और सुविधाएं बढ़ाता है। यह आशंका गलत नहीं कि मंदिरों को कब्जे में लेकर नेतावर्ग अपनी ताकत एवं आमदनी और बढ़ाना चाहें। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि जिस हिंदू समाज के बल पर भारतीय राज्यतंत्र दशकों से चल रहा है, उसी के हितों की लगातार

बलि चढ़ाई जाती रही है। स्वतंत्र भारत में ही हिंदुओं को मुस्लिम और ईसाई समुदायों की तुलना में हीन दर्जे में कर दिया गया, जो ब्रिटिश राज में भी नहीं था। स्वयं भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि हिंदुओं को मुस्लिमों, ईसाइयों की तुलना में कम शैक्षिक, धार्मिक, कानूनी अधिकार हैं। इस ओर संकेत करते हुए डॉ. आंबेडकर ने भारतीय संविधान को गैर-सेक्युलर कहा था, क्योंकि 'यह विभिन्न समुदायों के बीच भेदभाव करता है।' इसी मूल गड़बड़ी का नतीजा हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जा भी है। यह हिंदूवादी कहलाने वालों के शासन में भी जारी है।

जबकि सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जे को कई बार अनुचित कह चुका है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 'मंदिरों का संचालन और व्यवस्था भक्तों का काम है, सरकार का नहीं।' उसने चिदंबरम (तमिलनाडु) के नटराज मंदिर को सरकारी कब्जे से मुक्त करने का आदेश 2014 में दिया था। इसके अलावा पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में जस्टिस बोबडे ने कहा था, 'मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिर का संचालन करना चाहिए?' उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया कि सरकारी नियंत्रण के दौरान वहां अनमोल देव-मूर्तियों की चोरी की अनेक घटनाएं होती रही हैं। ऐसी स्थितियों का कारण भक्तों के पास अपने मंदिरों के संचालन का अधिकार न होना है। यह अधिकार राज्य ने छीन लिया और उसके अमले वैसे ही काम करते हैं, जैसे आम सरकारी विभाग। वे धार्मिक गतिविधियों, रीतियों में भी हस्तक्षेप करते हैं। सरकारी अफसरों को तो मात्र नागरिक शासन चलाने की ट्रेनिंग मिली है। इसलिए कोई अफसर अपने पूर्वग्रह, अज्ञान या मतवादी कारणों से हिंदू धर्म के प्रति उदासीनता या दुराग्रह भी दिखा सकता है। इस अनुभव के बावजूद सरकारें हिंदू मंदिरों पर दिनों-दिन कब्जा बढ़ा रही हैं। इनमें भाजपा सरकारें भी हैं। क्या इससे बड़ा धार्मिक अन्याय हो सकता है कि करीब चार लाख से अधिक मंदिरों पर सरकारी कब्जा है, किंतु एक भी चर्च या मस्जिद पर राज्य का नियंत्रण नहीं है? हिंदू समाज के अलावा शेष सभी समुदाय अपने-अपने धर्मस्थान स्वयं चलाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। यह भेदभाव हिंदू समुदाय को दिनोंदिन और दुर्बल, असहाय बनाने का उपाय है।

सर्वविदित है कि कुछ बाहरी पंथ भारत में हिंदू धर्म पर प्रहार करते रहे हैं। सदियों से छल-बल से हिंदुओं का मतांतरण कराते रहे हैं। अपने इलाकों में उन्हें मारते-भगाते रहे हैं। उन्हीं समुदायों को मंदिरों की आय से ही विशेष सहायता दी जाती है। आंध्र और कर्नाटक में हिंदू मंदिरों की आय से हज सब्सिडी देने की बात कई बार जाहिर हो चुकी है। यह तो सीधे-सीधे हिंदू धर्म पर चोट है।

राजकीय कब्जे वाले हिंदू मंदिरों के पुजारी सरकारी अफसरों के अनुचर बना दिए गए हैं। उन्हें अपने ही मंदिरों की देख-रेख से वंचित या बाधित कर दिया गया है। वे मंदिरों के पारंपरिक शैक्षिक, कला, संस्कृति या सेवा संबंधी कार्य नहीं कर सकते, जो सदियों से होते आ रहे थे, जैसे, पाठशालाएं, वेदशालाएं, गौशालाएं, चिकित्सालय, शास्त्रीय नृत्य आयोजन आदि। इस प्रकार भारत में हिंदू मंदिर के पुजारियों की तुलना में किसी मस्जिद के इमाम या चर्च के बिशप की सामाजिक स्थिति मजबूत होती गई। वे अपने समुदाय को समर्थ, सबल बनाने के लिए मस्जिद और चर्च का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह भी तुलनात्मक रूप से हिंदुओं के लिए एक गंभीर हानि है। यह हानि और अधिक खतरनाक होने वाली है इसे समय रहते समझना चाहिए।

मंदिरों में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया धन सरकार द्वारा लेना भी संविधान के अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन है। सरकारी कब्जे के कारण ही मंदिरों से सर्विस-टैक्स वसूला जाता है। यह मस्जिदों या चर्चों से नहीं वसूला जाता। कई मंदिरों में ऑडिट फीस, प्रशासन चलाने की फीस और दूसरे तरह के टैक्स वसूले जाते हैं। किसी-किसी मंदिर की आय का लगभग 65-70 फीसद तक सरकार हथिया लेती है। 1986-2005 के बीच तमिलनाडु में मंदिरों की हजारों एकड़ जमीन उनसे छिन गई। हजारों एकड़ पर अवैध अतिक्रमण हो चुका है। यह सब सरकारी कब्जे की व्यवस्था का नमूना है। याद रहे कि भारतीय परंपरा में किसी हिंदू राजा ने मंदिरों पर अधिकार या नियंत्रण नहीं जताया, न उनसे कर वसूला। धार्मिक कार्यों में राजा द्वारा हस्तक्षेप के उदाहरण नहीं मिलते। वे तो सहायता ही देते थे। मुगल काल में मंदिरों को तरह-तरह के राजकीय अत्याचार झेलने पड़ते थे। दुर्भाग्यवश स्वतंत्र भारत में भी हिंदू समुदाय को अपने धार्मिक-शैक्षिक-सांस्कृतिक संस्थान चलाने का वह अधिकार नहीं, जो अन्य को है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91
से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त, अस्पतालों को रोज देनी होगी खाली बेड की जानकारी

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बेहद घातक होने के बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ को अब जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं है। टीम-11 के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर बेहद सख्त थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त लहजे में सभी को निर्देश दिया कि इंजेक्शन रेमडेसिविर या फिर अन्य किसी भी दवा की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं है। इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ एनएसए के साथ गैंगस्टर एक्ट जैसी कार्रवाई करें। इसके साथ ही प्रदेश के हर अस्पताल को अब प्रतिदिन अपने खाली बेड की जानकारी जिला प्रशासन के माध्यम से शासन को देनी होगी। सभी अस्पताल रोज बताएंगे कि उनके पास कितने खाली बेड हैं।

खाली बेड्स के बारे में हर दिन जानकारी सार्वजनिक की जाए- सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अस्पतालों में खाली बेड्स के बारे में हर दिन जानकारी सार्वजनिक की जाए। इससे मरीजों के परिजनों को काफी सहूलियत होगी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की भूमिका इस कार्य में अत्यंत उपयोगी है। इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुखद है कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में 14 हजार से भी अधिक मरीज कोविड संक्रमण से ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। अतः सभी प्रदेशवासी धैर्य और संयम बनाये रखें। प्रदेश में उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं हों अथवा जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता, किसी भी चीज का अभाव नहीं है। कोविड के लक्षण दिखें तो टेस्ट कराएं, चिकित्सकों के निर्देशों का पालन करें। परिस्थितियों का आंकलन करते हुए सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। कोरोना कर्फ्यू और साप्ताहिक बंदी जैसे प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है। अब तो मास्क, सैनिटाइजर और दो गज दूरी जैसे कोविड प्रोटोकॉल को पूरी ईमानदारी से सभी अमल में लाया जाए। लापरवाह लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अपना लिया- प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार के बढ़ते

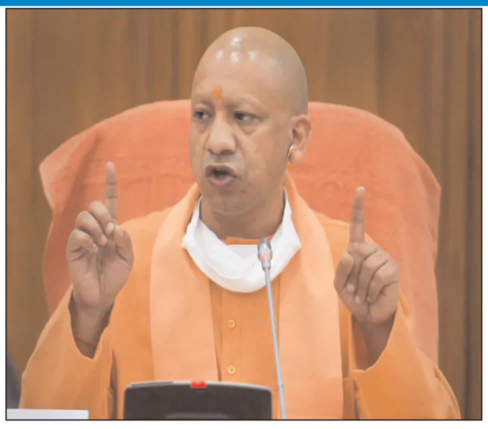

मामलों और प्रदेश सरकार बदइंतजामी के आरोपों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। कोरोना वायरस के संक्रमित होने के बाद भी नौ दिन का व्रत रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेमडेसिविर या फिर अन्य जीवनरक्षक दवाओं की प्रदेश में कहीं पर भी कालाबाजारी मिलने पर आरोपित के खिलाफ तत्काल ही एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और फैबीफ्लू जैसी जीवनरक्षक मानी जा रही दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए आवश्यक है कि इसकी लगातार निगरानी की जाए। ऐसी दवाओं और इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन एनएसए के तहत कार्रवाई करे। इसके साथ ही शासन के अफसर देश में हर जगह पर रेमडेसिविर उत्पादनकर्ता कंपनियों से लगातार संपर्क में रहें। उन्होंने कहा कि गुरुवार तक प्रदेश को 10,000 वॉयल और रेमडेसिविर प्राप्त हो जाएंगी। अब उन्होंने ने प्रतिदिन 50,000 वॉयल रेमडेसिविर की आपूर्ति के हिसाब से डिमांड भेजने का निर्देश दिया।

अभी व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन नहीं- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हर जगह मांग के अनुरूप ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार से आवंटित ऑक्सीजन को यथाशीघ्र प्रदेश में उपलब्ध कराया जाए। ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति में संतुलन बना रहे इसके लिए अब सभी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन का ऑडिट कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ त्वरित और कठोरतम कार्रवाई की जाए। अति गंभीर परिस्थिति को छोड़कर किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति न की जाए। केवल संस्थागत आपूर्ति ही होगी। सभी ऑक्सीजन रीफिल केंद्रों पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती की जाए। यह सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन का वितरण पारदर्शी ढंग से हो। ऑक्सीजन टैंकर को जीपीएस से जोड़ा जाए तथा प्लांट्स पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक विकास, एमएसएमई तथा गृह विभाग आपसी समन्वय से इस कार्य को करें। टैंकर/सिलिंडर का कोई अभाव नहीं है। प्रत्येक अस्पताल में न्यूनतम 36 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप होना चाहिए।

ऑक्सीजन उत्पादन और रीफिलिंग इकाइयों को मिले निर्बाध बिजली- सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी अस्पतालों, ऑक्सीजन उत्पादन और रीफिलिंग से जुड़ी इकाइयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा औद्योगिक इकाइयों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए गतिविधियां संचालित की जाएं। बेहतर कोविड प्रबंधन में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। लखनऊ सहित सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो। आईसीसीसी के माध्यम से बेड आवंटन की जानकारी, समय पर एम्बुलेंस की उपलब्धता आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक की प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही हर दिन रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू को सफल बनाने पर भी जोर दिया है। कोविड संक्रमितों के 50 फीसदी एंबुलेंस- मुख्यमंत्री ने डॉयल-108 एम्बुलेंस सेवा का 50 प्रतिशत उपयोग कोविड संक्रमितों के लिए करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस दौरान एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को कम करने की जरूरत बताई। टीकाकरण अभियान की करें तैयारी- मुख्यमंत्री ने ने कहा राज्य मंत्रिपरिषद ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के निःशुल्क कोविड टीकाकरण कराए जाने का निर्णय लिया है। कोविड से लड़ाई में यह सबसे अहम प्रयास होगा। स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में आवश्यक तैयारी प्रारंभ कर दे। स्वच्छता, सैनीटाइजेशन तथा फॉगिंग का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाए। इसके लिए फायर विभाग के वाहनों का उपयोग किया जाए। वर्तमान में प्रदेश में 77 हजार से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाये गए हैं। कंटेनमेंट जोन के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए। मास्क के अनिवार्य उपयोग के संबंध में प्रवर्तन की प्रभावी कार्यवाही की जाए।

संक्षिप्त खबर

कोरोना वायरस संक्रमण में रामबाण नहीं यह इंजेक्शन, इसे लगाने के बाद भी जान गंवा रहे मरीज

प्रयागराज । देश के साथ प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के जानलेवा होने के बीच में बेहद चर्चा में आए एंटी इंजेक्शन रेमडेसिविर की हकीकत कुछ अलग ही है। संक्रमितों के तीमारदार जहां इसको रामबाण मान रहे हैं, वहीं प्रख्यात चिकित्सकों की राय है कि इसको संजीवनी नहीं मानना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ ही संगमनगरी प्रयागराज में कुछ डाक्टर इसे तरजीह दे रहे हैं और इसके दुष्प्रचार का आलम ऐसा है कि इस एंटी वायरल इंजेक्शन रेमडेसिविर की दवा बाजार में इसकी कालाबाजारी हो रही है। प्रामाणिक तौर पर कोई भी प्रतिष्ठित डाक्टर यह कहने के लिए तैयार नहीं है कि इस इंजेक्शन से किसी संक्रमित की जान बची है। ऐसे भी कुछ संक्रमित हैं, जिन्हें छह डोज लगी पर उनके प्राण पखेरू नहीं बचाए जा सके।

कोरोना की दूसरी लहर जब से कहर बरपा रही है तब से रेमडेसिविर इंजेक्शन खास हो गया है। आलम यह है कि संक्रमित के तीमारदार इसके लिए एमआरपी (अधिकतम फुटकर मूल्य) से दो से तीन गुना कीमत भी देने के लिए तैयार रहते हैं। एक-एक इंजेक्शन बहुमूल्य हो गया है। गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले सरकारी अस्पतालों के डाक्टर नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि रेमडेसिविर रामबाण नहीं है। स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, तेज बहादुर सप्रू (बेली) अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में अब तक दो दर्जन से अधिक ऐसे संक्रमितों की मौत हो चुकी है जिनकी जान बचाने के लिए यह इंजेक्शन लगाया गया था। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस इंजेक्शन से जान बचने के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। इक्का-दुक्का केस अपवाद हो सकते हैं। इसे रामबाण बताते हुए दुष्प्रचार समझ से परे है।

पटियाला में महिला के चेहरे पर टेप लपेटकर हत्या, बेटे के आफिस के रास्ते घर में घुसे हत्यारे

पटियाला। लाहौरी गेट थाने के तहत विकास कालोनी में अज्ञात लोगों ने एक बुजुर्ग महिला की पूरे चेहरे पर टेप लपेटकर हत्या कर दी गई। महिला की पहचान 60 वर्षीय कमलेश रानी सिंगला के रूप में हुई है। कमलेश रानी का शव बुधवार सुबह उनके मंझले बेटे ने देखा, जो उनके बगल में बने मकान में रहता है। हत्यारे वारदात को अंजाम देने के लिए उनके मंझले बेटे के आफिस के जरिये घर में घुसे थे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच में मामला प्लांड मर्डर का लग रहा है, जिसे लूट दिखाने की कोशिश की गई है। हत्यारे वारदात को अंजाम देने के बाद घर में लगे सीसीटीवी के डीवीआर भी साथ ले गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए राजिंदरा अस्पताल भेज दिया गया है। लाहौरी गेट थाने की पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। कमलेश रानी के पति नरिंदर कुमार सिंगला बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन थे। उनका करीब एक साल पहले निधन हो गया था। उनके तीन बेटे हैं, जिनमें से दो बेटे शैरी सिंगला व सन्नी सिंगला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वकील हैं। मंझले बेटे हैरी सिंगला पटियाला जिला अदालत में वकील हैं। वे विकास कालोनी स्थित मकान में मां, पत्नी व दो बेटों के साथ रहते हैं।

मकान दो हिस्सों में बना है, एक हिस्सा हैरी के पास है। उन्होंने इसमें आफिस भी बना रखा है। हत्यारे इस आफिस के दरवाजे पर लगे शीशे को निकालने के बाद दरवाजा खोलकर अंदर घुसे। वे आफिस के अंदरूनी दरवाजे के जरिये कमलेश रानी के कमरे तक तक पहुंचे। वहां पर उनके सिर पर भारी वस्तु से वार करके जख्मी किया। फिर दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांधने के बाद पूरे चेहरे पर टेप लपेट दी, ताकि दम घुटने से मौत हो जाए। हत्यारों ने कमरे में अलमारी व अन्य हिस्सों का सामान बिखेरा हुआ था। मौके से कुछ सामान चोरी होने की आशंका है, लेकिन महिला के पहने कुछ गहने हत्यारे छोड़ गए।

एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल ने कहा कि मौके पर जांच के दौरान कुछ सुराग मिले हैं, जिसके बाद छह सदस्यीय एसआइटी बना दी है। इसमें एसपी सिटी आइपीएस वरुण शर्मा, एसपी (डी) हरमीत हुंदल, डीएसपी (डी) कृष्ण पैंथे, डीएसपी घनौर जसविंदर टिवाणा, सीआइए इंचार्ज राहुल कौशल व थाना लाहौरी गेट इंचार्ज जसप्रीत सिंह को शामिल किया है।

रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी, शिकायतों पर प्रशासन की टीम ने मेडिकल पर मारा छापा

देहरादून । रेमडेसिविर दवा की किल्लत के बीच इसकी कालाबाजारी की शिकायत भी निरंतर मिल रही है। विशेषकर रेसकोर्स चौक स्थित रिंकू मेडिकोज के बारे में कालाबाजारी की बात सामने आ रही है। लिहाजा, जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम ने बुधवार को यहां छापेमारी की। जिलाधिकारी के निर्देश पर एक टीम सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान और दूसरी टीम एसडीएम सदर गोपालराम बिनवाल के नेतृत्व में बनाई गई। सिटी मजिस्ट्रेट की टीम ने मेडिकल स्टोर, जबकि एसडीएम की टीम ने मेडिकोज संचालक के रेसकोर्स स्थित घर पर छापा मारा। हालांकि, स्टोर व घर से रेमडेसिविर दवा बरामद नहीं की जा सकी। सिटी मजिस्ट्रेट चौहान ने बताया कि दवा कहीं अन्यत्र भी छिपाई जा सकती है। ऐसे में गोपनीय आधार पर उसका भी पता किया जा रहा है। छापेमारी में सीओ सिटी, सीओ नेहरू कॉलोनी समेत स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अधिकारी शामिल रहे।

दोपहर दो बजे से व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने के जिला प्रशासन के फैसले से व्यापारी खुश नहीं हैं। उनका तर्क है कि जिला प्रशासन ने कर्फ्यू का समय शाम सात बजे से किया है और दुकानें दोपहर दो बजे बंद करवा दी गई हैं। केवल चार घंटे में व्यापारी क्या कमाएंगे और क्या अपने कर्मचारियों को वेतन देंगे। व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि जीवन भी जरूरी है और आजीविका भी, लेकिन दून जिला प्रशासन आजीविका को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। पहले ही छोटे व्यापारी पिछले साल के लॉकडाउन से हुए घाटे से उबर नहीं पाए हैं। व्यापारी वर्ग कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर प्रशासन के साथ चलने को तैयार है, लेकिन परिवार का भरण पोषण व दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन का प्रबंध तो करना ही होगा। उन्होंने जिलाधिकारी से बाजार का समय बढ़ाने की मांग की है। दून वैली महानगर उद्योग व्यायार मंडल के अध्यक्ष पंकज मैसोन ने कहा कि दो बजे तक दुकानदार क्या व्यापार करेंगे। जब कर्फ्यू सात बजे से है तो कम से कम शाम छह बजे तक तो दुकानें खुली रखी जा सकती थीं। उधर, दून महानगर व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील कुमार बंगा ने कहा कि वाहन सात बजे तक दौड़ते रहेंगे और दुकानें दो बजे बंद हो जाएंगी, यह ठीक नहीं है। हजारों व्यापारी पहले ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

सीएम के बाद यूपी के डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा भी कोरोना संक्रमित, पत्नी सहित होम आइसोलेट

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा भी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में हैं। डॉ. दिनेश शर्मा अपनी पत्नी सहित संक्रमित होने के बाद होम आइसोलेशन में हैं। डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने ट्वीट से संक्रमित होने की जानकारी दी है। डॉ. दिनेश शर्मा लखनऊ में ऐशबाग में मास्टर कन्हैया लाल रोड पर अपने पैतृक आवास में रहते हैं।

उत्तर प्रदेश में तेजी से पांव जमा चुकी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर किसी को भी अपने चपेट में लेने से छोड़ नहीं रही है। इससे न तो मुख्यमंत्री ही बच सके और न ही डिप्टी सीएम। अधिकारी के साथ खिलाड़ी भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। शासन के शीर्ष अधिकारी भी इसकी चपेट में आने के बाद या तो होम आइसोलेशन में हैं या फिर किसी अस्पताल में भर्ती हैं।

उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने ट्वीट के माध्यम से अपने और अपनी पत्नी के कोरोना संक्रमित हो जाने की खबर दी है। इसके साथ ही यह जानकारी भी दी है कि वह अभी होम आइसोलेशन में हैं। प्रदेश के उच्च तथा माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा से विभाग के दो दर्जन से अधिक अधिकारी पहले से ही संक्रमित हैं।

डॉ. शर्मा ने लोगों से अपील की है कि जो भी बीते कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं, वह आइसोलेट हो जाएं और कोरोना जांच जरूर करा लें। डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने जानकारी दी है कि उनकी और पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है। दोनों ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। डॉक्टर्स के परामर्श का पालन कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि पिछले कुछ दिन में जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, वो भी जांच करा लें और कोविड गाईडलाईन का पालन करें।

सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक हफ्ते पहले हुए थे संक्रमित- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट भी बीती 14 अप्रैल को पॉजिटिव आई थी। उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से जनता तक जानकारी पहुंचाई थी कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं।

बुलंदशहर के बाद उन्नाव, कासगंज व सोनभद्र के एसपी भी कोरोना वायरस से संक्रमित

लखनऊ । कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के साथ ही साथ जिले की कानून-व्यवस्था को संभालने के जिम्मेदार भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। बुलंदशहर के बाद उन्नाव, कासगंज और सोनभद्र के एसपी कोरोना पॉजिटिव होने के कारण होम आइसोलेशन में हैं। इन जिलों की व्यवस्था संभालने के लिए अन्य जिलों के एसपी को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश के संक्रमित होने के कारण डॉ. रोशन जैकब इन दिनों लखनऊ की प्रभारी डीएम हैं।

प्रदेश में उन्नाव, कासगंज तथा सोनभद्र के एसपी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अब शासन ने स्वस्थ होने तक अन्य अफसरों को इन जिलों का चार्ज सौंपा है। लखनऊ के बाद अब मैनपुरी में भी जिलाधिकारी और उनकी पत्नी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इतना ही नहीं मैनपुरी के एसपी में भी कोरोना संक्रमण लक्षण हैं। उन्नाव के एसपी का अतिरिक्त प्रभार आइपीएस अफसर आशीष तिवारी को सौंपा गया है। वह अब उन्नाव के एसपी सुरेश राव ए कुलकर्णी के स्वस्थ होने तक सेनानायक एसएसएफ, लखनऊ पद के साथ उन्नाव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। इसी तरह से कासगंज के एसपी मनोज कुमार सोनकर के स्वस्थ होने तक एसपी सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ पद के कार्यरत कुंवर अनुपम सिंह कासगंज का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।

सोनभद्र के एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनके जिले का अतिरिक्त प्रभार सेनानायक चतुर्थ वाहिनी पीएसी सुधा सिंह को सौंपा गया है। मैनपुरी में डीएम मैनपुरी डीएम और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इनके अलावा सीडीओ इंशा और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ऋषिराज में भी कोरोनावायरस के लक्षण है। एसपी मैनपुरी अविनाश पांडे में भी कोरोना के लक्षण हैं। पंचायत चुनाव ड्यूटी से लौटे 15 फीसदी पुलिसकर्मी संक्रमित- प्रदेश में पंचायत चुनावों से लौटे पुलिस ज़र्मियों में से 10 से 15 प्रतिशत पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाये गए हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ ही पुलिसर्ज़मियों को कोरोना संक्रमण से बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। प्रयागराज में डीआईजी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी के निर्देश पर जहां सभी थानों, चौकियों, पुलिस लाइन और कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई है। वहीं नियमित सेनैटाइजेशन के भी निर्देश दिये गए हैं। पुलिस ज़र्मियों के कोविड पॉजिटिव आने पर उन्हें क्वारेंटाइन किया जा रहा है और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है।

संकट में जनता का मनोबल गिराने वाला काम करने वालों को मिले सजा: योगी

लखनऊ । देश के साथ ही प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बेहद भयावह होने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की जनता को उचित चिकित्सा सुविधा देने के साथ ही इनके हर प्रकार के कष्ट को कम करने के प्रयास में हैं। टीम-11 के साथ प्रतिदिन कोविड के उत्तर प्रदेश में प्रभाव पर चर्चा करने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ इसके दुष्प्रभाव को कम करने की जुगत की तलाश में हैं। उनका सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि संकट की घड़ी में जनता का मनोबल गिराने वालों को सख्त सजा दें। इनमें दवा की कालाबाजारी करने के साथ ही ऑक्सीजन या अन्य बेहद जरूरी उत्पाद की जमाखोरी करने वालों को भी शामिल करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एंबुलेंस सेवा का संचालन बेहतर किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए कि एम्बुलेंस सेवाएं सुचारु ढंग से काम करें। वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कोविड उपचार से जुड़े संस्थान, स्थानीय प्रशासन से समन्वय बनाकर काम करें। ऑक्सीजन या किसी जीवनरक्षक दवा के नाम पर जनता का मनोबल गिराने वाला काम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी व कानपुर नगर में लगातार कोविड बेड बढ़ाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की अद्यतन जानकारी के साथ-साथ बेड आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाए। इसके साथ आक्सीजन और रेमडेसिविर सहित जीवनरक्षक दवाओं की सुचारू आपूर्ति पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि निजी और सरकारी यानी सभी कोविड अस्पतालों के लिए एक-एक नोडल अधिकारी की भी तैनाती करें।

हर कोविड अस्पताल की निगरानी करें नोडल अधिकारी: होम आइसोलेशन में रहते हुए कोविड प्रबंधन संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड संक्रमितों की भर्ती और इलाज में मनमानी पर सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए हर निजी अस्पताल के लिए नोडल अधिकारी बनाने का फैसला लिया है। होम आइसोलेशन में रहते हुए कोविड प्रबंधन संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि लखनऊ के केजीएमयू डेडिकेटेड अस्पताल में नोडल अधिकारी कैंप करें। लखनऊ के एरा, इंटीग्रल, टीएस मिश्रा, हिंद, मेयो, प्रसाद व सक्सेना निजी मेडिकल कालेजों को राज्य सरकार ने कोविड उपचार के लिए टेकओवर किया है। इन मेडिकल कालेजों की निगरानी प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी करेंगे।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर की समीक्षा कर लगातार बेड बढ़ाने का निर्देश दिया। यहां पर आक्सीजन और रेमडेसिविर सहित जीवनरक्षक दवाओं की सुचारू आपूर्ति पर जोर देते दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर के अधिकारी अपने प्रभारी मंत्री से मार्गदर्शन लेते हुए कोरोना नियंत्रण के लिए हर स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को और बेहतर करें। उन्होंने कहा कि लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज व वाराणसी में मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पतालों में आक्सीजन प्लांट की स्थापना की प्रक्रिया की समीक्षा प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री करेंगे। कोविड अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जानकारी के साथ-साथ बेड आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाए।

अधिकारी अपने प्रभारी मंत्री से मार्गदर्शन लेते हुए कोरोना नियंत्रण के लिए हर स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को और बेहतर करें। आक्सीजन, रेमडेसिविर या अन्य जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वाले तत्वों के खिलाफ छापेमारी कर इनके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। पुलिस अधिकारी कंटेनमेंट जोन के प्रविधानों को इन जिलों में प्रभावी ढंग से लागू कराएं। प्रत्येक गांव और वार्ड में निगरानी समितियों को सक्रिय रखने के साथ ही शत-प्रतिशत कान्टैक्ट ट्रेसिंग के निर्देश दिए।

लखनऊ में शादी के बाद नकदी और जेवर समेट कर लुटेरी दुल्हन फरार, मामला दर्ज

लखनऊ । मड़ियांव क्षेत्र में कापरेंटर का काम करने वाले मनोज कुमार शर्मा को पड़ोसी ने उसको शादी कराने के पहले सपने दिखाए। इसके बाद ब्लैकमेल करके रुपये ऐंठता रहा। मनोज के दबाव बनाने पर उसने एक मंदिर में युवती से शादी भी करा दी। कुछ दिन युवती घर के जेवर, नकदी और कपड़े लेकर फरार हो गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मड़ियांव के ककौली गांव निवासी मनोज कुमार कारपेंटर का काम करते हैं। मनोज ने बताया कि मोहल्ले में रहने वाले संतराम से उनकी अच्छी दोस्ती है। संतराम ने उसकी शादी कराने का झांसा दिया और कहा कि उसके संपर्क में एक अच्छी लड़की है। आरोप है कि शादी का झांसा देकर संतराम उनसे रुपये भी ऐंठता रहा। कई माह बीत जाने के बाद भी जब शादी नहीं कराई तो संतराम पर दबाव बनाना शुरू किया। इसके बाद संतराम उन्हें बस्ती लेकर गया। वहां अंशिका नाम की एक युवती से मिलवाया और एक मंदिर में 17 मार्च को शादी करवा दी। शादी के दौरान मौके पर एक बुजुर्ग महिला और पुरुष भी मौजूद थे। उन्होंने कन्यादान किया उन्हें युवती के माता पिता बताया गया। इसके बाद लड़की विदा होकर घर आई, पर किसी ने यह नहीं बताया कि युवती कहां की रहने वाली है। युवती के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई।

पीड़ित मनोज के मुताबिक सोमवार को जब वह सोकर उठा तो पत्नी अंशिका घर पर नहीं थी। बक्से और अलमारी खुली पड़ी थी। कीमती कपड़े, जेवर और 20 हजार रुपये गायब थे। इसके बाद काफी तलाश के बाद भी अंशिका का कुछ पता नहीं चला। मामले की तहरीर लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस ने टरका दिया।

कोरोना को ले पटना हाईकोर्ट का आदेश- सरकार बताए कितने बेड खाली

पटना । कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण, अस्पतालों में ऑक्सीजन एवं बेड की कमी की खबरों के बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि वह प्रत्येक दिन आम लोगों को बताए कि किस अस्तपाल में कितने बेड खाली हैं। यह भी कि राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, कितनी जरूरत है और कितना उपलब्ध है। पूरा ब्योरा प्रत्येक दिन आमलोग को बताया जाए, ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। अदालत ने सरकार को पूरे ब्योरे के साथ अगली तारीख को तलब किया है। अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह एवं न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक एवं गौरव कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका पर बुधवार की शाम में सुनवाई की। इस दौरान पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्?थान के निदेशक एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव ने नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल (एनएमसीएच) में संक्रमितों के इलाज के बारे में कोर्ट को बताया। उनलोगों ने कहा कि निरीक्षण के क्रम में पाया कि अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के लिए चार सौ बेड की व्यवस्था है, जिनमें करीब दो सौ बेड खाली हैं।

इसपर अदालत ने हैरानी जताई और कहा कि अगर दो सौ बेड खाली हैं तो फिर कैसे कहा जा रहा है कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है और उन्हें भटकना पड़ रहा है। अदालत ने कहा कि मीडिया में तो खबरें आ रही हैं कि मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। बेड के लिए अस्पताल दर अस्पताल लोगों को भटकना पड़ रहा है। अदालत ने कहा कि सरकार अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करते रहे और इसकी जानकारी कोर्ट को भी दे। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के बारे में भी अदालत को बताया गया।

पटना के अस्पताल ने कोरोना मरीजों के इलाज में इस इंजेक्शन पर लगाया बैन

पटना । कोरोनावायरस संक्रमण के इलाज के लिए तीन हजार रुपये के जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 40-50 हजार तक की कालाबाजारी हो रही थी, वह इलाज में किसी काम का नहीं निकला। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एनएमसीएच के अधीक्षक डॉ. विनोद कुमार सिंह ने अस्पताल के सभी डॉक्टरों को निर्देशित किया है कि वे कोरोनावायरस संक्रमित मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लिखें।

विदित हो कि देश भर में कोरोना संक्रमितों को दिए जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस इंजेक्शन की मांग का लाभ कालाबाजारी भी उठा रहे हैं। तीन हजार रुपये मूल्य की यह दवा 50 हजार रुपये तक में बेची जा रही है। कालाबाजार में इसकी कीमत मरीज की स्थिति व मांग को देखते हुए तय की जा रही है। मांग को देखते हुए केंद्र सरकार को तो पहल करनी ही पड़ी, बिहार सरकार भी इसे मरीजों को उपलब्ध कराने में जुटी रही।

इस बीच कोरोनावायरस संक्रमण को लेकर पटना हाईकोर्ट में दर्ज एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर को लेकर सरकार से जवाब मांगा, तब पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक ने बताया कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना के मरीजों के इलाज में नहीं किया जा रहा है। यह इलाज में बेअसर है। इसके बाद अब एनएमसीएच ने इसपर बैन लगा दिया है।

डॉ अलका से पूछताछ में मिले अहम सुराग, राज उगलवाने के लिए गिरफ्तारी टालती रही बाराबंकी पुलिस!

बाराबंकी । एंबुलेंस पंजीयन मामले में नामजद डॉ. अलका राय की गिरफ्तारी में देरी की वजह पुलिस का उनसे राज उगलवाना माना जा रहा है। एंबुलेंस प्रकरण में नाम आने के बाद से ही पुलिस उनके संपर्क में थी और बयान भी ले चुकी थी। इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं की थी। उन्हीं के बयान के आधार मुकदमे में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी उनके करीबियों को शामिल किया गया था। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत उनकी गिरफ्तारी जल्दी करनी पड़ी है, जबकि पुलिस को उनसे अभी और जानकारी हासिल करनी है। आगे की कार्रवाई पुलिस उनको रिमांड पर लेकर करेगी। तथ्यों की पुष्टि होते ही पुलिस करेगी और गिरफ्तारियां- फर्जी दस्तावेज के जरिये एंबुलेंस का पंजीयन होने की बात सामने आने पर दो अप्रैल को मऊ की डा. अलका राय के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसके बाद तीन अप्रैल को मऊ के लिए पुलिस टीम रवाना हो गई थी और वहां उनसे पूछताछ की थी। इसमें टीम को अहम सुराग मिले थे और इसी आधार पर मुकदमे में अन्य के नाम शामिल किए गए और राजनाथ यादव की गिरफ्तारी भी की गई थी। पुलिस को अलका से अभी और राज उगलवाने थे। शायद इसीलिए पुलिस उनकी गिरफ्तारी टाल रही थी। अगर ऐसा नहीं था तो पुलिस पहले दिन ही उनकी गिरफ्तारी कर सकती थी। अलका से पूछताछ में पुलिस को अन्य लोगों के संलिप्तता की भी जानकारी मिली है। पुलिस उनसे संबंधित तथ्यों की गहनता से पड़ताल में जुट गई है। पुष्टि होते ही अन्य की भी गिरफ्तारी की जाएगी। बताया जाता है कि पुलिस टीम को डा अलका राय के फरार होने का अंदेशा था। इसलिए उनकी गिरफ्तारी में शीघ्रता की गई। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि पूछताछ में जिले और गैर जनपद के कई नाम प्रकाश में आए हैं। प्रकरण में उनकी भूमिका की गहनता से पड़ताल की जा रही है। संलिप्तता की पुष्टि होने पर गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस अलका राय और जेल में बंद अन्य आरोपितों को जल्द ही रिमांड पर लेकर और जानकारी हासिल करेगी।

देश भर में बढ़ते कोरोनावायरस के मामलों के बीच कोलकाता के एक स्वास्थ्य केंद्र में एक लाभार्थी कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करते हुए।

ऑक्सीजन मास्क पहने एक कोविड -19 मरीज, मुंबई के दहिसर में जंबो कोविड केंद्र में भर्ती होने के लिए।

लाभार्थी कोरोनोवायरस मामलों में कोविड -19 वैक्सीन की खुराक प्राप्त करने के लिए गुवाहाटी में एक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतीक्षा करते हुए।

एक नजर

देश के हितों को नुकसान पहुंचा रहे अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी

जम्मू । जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी ओहदों पर तैनात होकर देशविरोधी तत्वों को शह देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए पांच सदस्यीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क प्रशासन में काली भेड़ों की पहचान कर उनके खिलाफ सारे सुबूत जुटाकर उन्हें नौकरी से बाहर निकालने के लिए मुख्यसचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौंपेगी। मुख्यसचिव वाली कमेटी के सदस्यों में गृह विभाग्र के सचिव, सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक व कानून विभाग के प्रशासनिक सचिव शामिल हैं। यह कमेटी भारतीय संविधान की धारा 311 (2) (सी) के तहत देशविरोधी गतिविधियों में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों को निकालने के लिए प्राधिकृत है।

सरकार ने यह कमेटी ऐसी पुख्ता जानकारी मिलने के बाद बनाई थी कि कुछ सरकारी कर्मचारी जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लोगों को देश के खिलाफ भड़का रहे हैं। कश्मीर केंद्रित सरकारों के कार्यकाल के दौरान देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों को नजरंअदाज किया जाता रहा है। ऐसे में वर्ष 2020 में इन अधिकारियों, कर्मचारियों को घेरने के लिए सरकार की कार्रवाई तेज हो गई थी। ऐसे में मुख्यसचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को कार्रवाई करने में मदद देने के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में सीआईडी ने ऐसे 500 के करीब अधिकारियों, कर्मचारियों की सूची बनाई है जिनके खिलाफ देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने के पक्के सुबूत हैं। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है।

जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग के सीआईडी विंग के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता वाली यह कमेटी भारतीय संविधान की धारा 311 (2) (सी) के तहत देशविरोधी गतिविधियों में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों का रिकार्ड तैयार करेगी। यह टास्क फोर्स टेरर मानिटरिंग ग्रुप के साथ समन्वय बनाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सुबूत जुटाएगी। बुधवार को बनाई गई टास्क फोर्स के अन्य सदस्यों में जम्मू व कश्मीर के आईजीपी, अतिरिक्त सचिव स्तर का ग्रह विभाग का एक अधिकारी, कानून विभाग व अतिरिक्त सचिव व संबधित विभाग का एक अधिकारी शामिल है। यह कमेटी तय समय अवधि में कार्रवाई करते हुए मुख्यसचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी को अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर कमेटी यह फैसला करेगी कि उसे सीधे नौकरी से निकालना है या पद कम करना है।

कोविड की पाबंदियों के बीच धर्मशाला के विधायक एचएएस अधिकारी ओशिन से लेंगे सात फेरे

धर्मशाला । धर्मशाला के युवा विधायक विशाल नेहरिया 26 अप्रैल को परिण्य सूत्र में बंधने जा रहे हैं। विशाल नेहरिया एचएएस अधिकारी ओशिन शर्मा के साथ सात फेरे लेंगे। ओशिन शाहपुर हलके के रैत की रहने वाली हैं। ओशिन के पिता भुवनेश शर्मा नायब तहसीलदार हैं, जबकि माता सुंदरी शर्मा राजस्व विभाग बंदोबस्त कार्यालय धर्मशाला में तैनात हैं। बताया जा रहा है कि शादी समारोह शाहपुर के गोजू में एक मैरिज पैलेस में होगा। विधायक की शादी को लेकर उनके कार्यकर्ताओं व मित्रों में काफी उत्साह है। साथ ही कोविड-19 की बंदिशें व चुनौतियां भी इस शादी के लिए एक परेशानी जरूर हैं।

लेकिन विधायक विशाल नेहरिया 26 अप्रैल को ओशिन शर्मा के साथ परिण्य सूत्र में बंधेंगे। इसके लिए दोनों परिवारों की ओर से बहुत ज्यादा तैयारियां की जा चुकी हैं। धर्मशाला में विशाल नेहरिया समर्थकों में भी खुशी है, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन भी इस उत्सव में कहीं न कहीं चुनौती रहेंगी।

रंगदारी गिरोह शहर के कई व्यापारियों से वसूल चुका है करोड़ों रुपये

जम्मू । मंदिरों के शहर जम्मू के नामीगिरामी व्यापारियों से रंगदारी वसूलने वाले गिरोह के 11 सदस्यों को गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी गिरोह के कुछ गुर्गो सदस्यों की गिरफ्तारी बाकी है।गिरोह के मास्टर माइंड राजा और रायल सिंह से पुलिस ने बुधवार को गांधी नगर पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर उन व्यापारियों के नाम जानने चाहे जिनसे रंगदारी वसूली जाती थी।

पुलिस को कुछ अहम जानकारी मिली है, जिसमें गिरोह के सरगना राजा ने शहर के कुछ जानेमाने ट्रांसपोर्टरों, आभूषण कारोबारियों, रीयल स्टेट के ठेकेदारों और अन्य आर्थिक तौर से सम्पन्न व्यापारियों से रंगदारी वसूली है।जिन व्यापारियों ने गिरोह को रंगदारी दी है, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि ऐसे व्यापारी खुलकर सामने नही आना चाहते। गिरोह में करीब 26 लोग है, जिन्हें अलग अलग काम सौंपा गया।कुछ सदस्य व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकाते थे।वसूली का काम अलग बदमाशों को सौंप जाता था।

रंगदारी की रकम रायल सिंह समेत गिरोह के अन्य सदस्यों में उनके काम के मुताबिक बांटी जाती थी। जम्मू के व्यापार नागर सिंह उर्फ नागों से भी 21 मार्च और 14 मार्च को दो बार 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे देने से मना किया तो उनके घर पर 3 अप्रैल को गिरोह के सरगना राजा के साथी बबलू उर्फ लंगडा और बबलू निवासी आरएसपुरा ने घर के बाहर से नागों के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। जिसमें कोई जानी नुकसान नही हुआ था। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि रायल सिंह पर जब अमनदीप सिंह हत्या का मुकदमा चल रहा था तब राजा अकसर उससे मिलने कोर्ट और जेल में मिलने जाता था। इस बारे में एसएसपी जम्मू चंदन कोहली प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं।

जम्मू विवि ने बढ़ाई टीचिंग स्टाफ के आवेदन की तिथि

जम्मू । कोरोना महामारी के चलते जम्मू विश्वविद्यालय ने टीचिंग स्टाफ के लिए निकाले गए आवेदनों की तिथि को आगे बढ़ा दिया है। पहले इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल रखी गई थी लेकिन अब इसे 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। जम्मू विश्वविद्यालय ने विभिन्न विषयों के लेक्चरर, टीचिंग असिस्टेंट के लिए आवेदन मांगे थे जिनमें विवि के मेन कैंपस के अलावा डिस्टेंस एजूकेशन, लॉ स्कूल, भद्रवाह कैंपस, कठुआ कैंपस, किश्तवाड़ कैंपस, रामनगर कैंपस, रियासी कैंपस, पुंछ कैंपस, ऊधमपुर कैंपस के लिए पद भरे जाने थे। यह नियुक्तियां अस्थायी की जानी है जो वर्ष 2021-22 के सत्र के लिए ही अनुबंध के आधार पर होंगी।

जम्मू विवि नया शिक्षा सत्र शुरू करने की पूरी तैयारी में था और कक्षाओं के शुरू होने से पहले इस स्टाफ की नियुक्ति करनी थी लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी भी बंद हो गई जिस कारण यह नियुक्तियां भी समय पर नहीं हो पाई। जम्मू यूनिवर्सिटी में कुछ विद्यार्थी व स्टाफ सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले थ्रे जिसके बाद विवि को बंद कर दिया गया जबकि बाद में इसे खोल दिया गया। इस समय यूनिवर्सिटी में सभी प्रकार की शिक्षा संबंधी गतिविधियां बंद हैं जबकि प्रशासनिक काम चल रहे हैं।

मांग के अनुसार नहीं मिल रही ऑक्सीजन, प्रत्येक तीसरे कोरोना मरीज को पड़ रही है जरूरत

जयपुर । राजस्थान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर इतनी घातक हो गई कि प्रत्येक तीसरे मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। संक्रमण सीधे फेंफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता को क्षीण कर रहा है । दूसरी लहर में एक्टिव केस एक लाख पार कर गए। ऐसे में प्रदेश में इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के लिए पूर्ति की जा सके। ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना मरीज मुश्किल में आ सकते हैं। अभी करीब 250 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन 100 टन के करीब ऑक्सीजन मिल रहा है। बढ़ते मरीजों के कारण प्रतिदिन ऑक्सीजन की जरूरत 10 से 20 टन लगातार बढ़ रही है।

प्रतिदिन 250 टन ऑक्सीजन की जरूरत - ऑक्सीजन और रेमडेसिवर इंजेक्शन की बढ़ती मांग व कम होती आपूर्ति को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉ.रघु शर्मा ने एक बार फिर केंद्र सरकार से सप्लाई बढ़ाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा तत्काल 120 टन मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य को अभी 100 मैट्रिक टन भी रोजाना आपूर्ति नहीं हो पा रही है,जबकि जरूरत प्रतिदिन 250 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। बढ़ते मरीजों को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने निजी अस्पतालों में 50 फीसदी बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए हैं। पहले ये 25 फीसदी ही थे।

रेमडेसिवर इंजेक्शन की बढ़ी मांग -अगर संक्रमण बढ़ने की रफ्तार यही रही तो इस माह के अंत तक ऑक्सीजन का उपभोग 350 टन प्रतिदिन तक पहुंच सकता है। इसी बीच कोरोना पीड़ितों के उपचार में काम आने वाली महत्वपूर्ण दवा रेमडेसिवर इंजेक्शन की मांग बढ़ी है। प्रदेश में पीड़ितों की संख्या बढ़ने पर पिछले दो सप्ताह में 1 लाख 5 हजार इंजेक्शन खरीदने के आदेश तीन बड़ी कंपनियों को दिए गए हैं। लेकिन अब तक 18000 के करीब इंजेक्शन ही मिले हैं।

बढ़ायी गई बेड की क्षमता - जयपुर स्थित प्रदेश के सबसे बड़े राजस्थान मेडिकल हेल्थ विवि.में बेड्स की क्षमता 1200 से बढ़ाकर 1400 की गई है। जयपुरिया अस्पताल में भी बेड बढ़ाए गए है। सवाईमानसिंह में नया कोविड सेंटर बनाया गया है। संभागीय मुख्यालयों पर जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। सरकार ने ऑसीजन सिलेंडर और जीवनदायिनी दवाओं कर कालाबाजारी रोकने के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की है।

इंजेक्शन और दवाओं की कालाबाजारी बढ़ी- कोरोना संक्रमण में संजीवनी माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन,एजिथ्रोमाइसिन सहित अन्य आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी बढ़ गई है । इसको देखते हुए पुलिस और चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीमें छापेमारी कर रही है। एक दिन पहले इस टीम ने जयपुर के पांच दर्जन मेडिकल स्टोर्स पर छापेमार कर गुडगांव से 2200 में खरीदे गए इंजेक्शन 15000 रूपए में बेचे जा रहे थे । इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है । बुधउदयपुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज के दो स्टूडेंट्स को इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उधर भाजपा विधायक व पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने में नाकाम साबित हो रही है ।

महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक मई तक लगाई गई कड़ी पाबंदी

मुंबई । महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की विभीषिका से निपटने के लिए राज्य सरकार ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। लेकिन जैसी कि संभावना व्यक्त की जा रही थी, लॉकडाउन लगाने से कतरा गई है।

मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लगभग सभी मंत्रियों ने सरकार से 15 दिन के लाकडाउन की मांग की थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि लॉकडाउन का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर छोड़ दिया गया है। वह बुधवार को आठ बजे के बाद इस संबंध में कोई घोषणा कर सकते हैं। मंगलवार को ही रात 8.45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए राज्यों को लॉकडाउन जैसा कदम उठाने से बचने की सलाह दी थी। माना जा रहा है कि इसी सलाह पर अमल करते हुए महाराष्ट्र ने लॉकडाउन के बजाय सख्त पाबंदियों का मार्ग चुना है। ये पाबंदियां फिलहाल 22 मार्च को रात आठ बजे से एक मई की सुबह सात बजे तक लागू रहेंगी।

मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की ओर से जारी नए निर्देशों में अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों को अब 50 फीसद के बजाय 15 फीसद क्षमता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन निजी कार्यालयों को अब तक 50 फीसद क्षमता के साथ काम करने की छूट दी गई थी, उन्हें भी 15 फीसद कर्मचारियों के साथ ही काम करने को कहा गया है। उन्हें 15 फीसद व पांच कर्मचारियों में से जो अधिक होगा, वही मानना होगा। यात्रा के लिए जारी नियमों में लोग अपने निजी वाहनों में चालक को छोड़कर क्षमता की आधी सीटों पर सवारियां बैठ सकेंगी। निजी बसों को 50 फीसद क्षमता के साथ सवारियां ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन ये बसें शहर में अधिकतम दो स्टाप ही ले सकेंगी। साथ ही, जहां-जहां यात्रियों को उतारेंगी, वहां यात्रियों के हाथ पर 14 दिन क्वारंटाइन रहने की मुहर लगानी होगी।

यदि किसी यात्री के शरीर का तापमान अधिक पाया जाता है, तो उसे कोविड केयर सेंटर या किसी अस्पताल में भेजना होगा। यदि कोई बस आपरेटर इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसे 10,000 रुपये दंड भरना होगा। एक जिले से दूसरे जिले या शहर में जाने के लिए आपदा प्रबंधन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वैवाहिक समारोह किसी एक ही हाल में सिर्फ 25 लोगों के साथ संपन्न करने होंगे। इससे अधिक व्यक्ति पाए जाने पर आयोजक को 50,000 रुपये दंड भरना पड़ सकता है।

पुरी जगन्नाथ रथयात्रा की तैयारी आरंभ, रथ निर्माण के लिए लकड़ी काटने का कार्य शुरू

कटक । विश्व प्रसिद्ध पुरी रथयात्रा के लिए बुधवार पवित्र रामनवमी के मौके पर रथ निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। कटक नुआपड़ा में मौजूद वन उन्नयन निगम के खपुरिया करत कल यानी सॉ मिल (आरा मशीन) में चतुर्धा मूर्ति की रथ निर्माण के लिए लकड़ी काटने का कार्य शुरू हुआ है। हर साल की भांति इस साल भी पुरी जगन्नाथ मंदिर से आज्ञामाल लाए जाने के बाद नयागड़ जिला दसपल्ला जंगल से लाए जाने वाली बड़ी-बड़ी लकड़ियों को पहले विधि अनुसार पूजा अर्चना की गई। महाप्रभु जी के नाम पर हरि बोल देते हुए संकीर्तन का आयोजित किया गया।

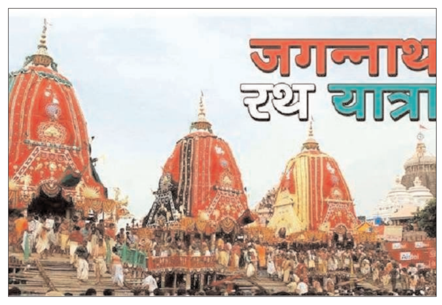

पुरी से आए महाप्रभु जी के रथ काठ महाराणा लक्ष्मण महापात्र के द्वारा पूजा अर्चना की गई थी। इस मौके पर कटक के जिलाधीश भवानी शंकर चयनी, पुरी जगन्नाथ मंदिर नीति पूजा प्रशासक जितेंद्र कुमार साहू, वरिष्ठ प्रशासक सुदर्शन मेकाअप, भोई सरदार रवि भोई प्रमुख मौजूद थे।

इस मौके पर खपूरिया सॉ मिल परिसर में एक विशेष आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला। सॉ मिल के अधिकारी भागवत साहू, श्रीनाथ सुबुद्धि, शिवचरण बारिक, कर्मचारी चक्रधर नाथ, नरेश साहू बृज नाथ, सरोज मोहंती, फारेस्टर चंद्रशेखर पंडा, रेंज ऑफिसर दुर्गा चरण साहू प्रमुख मौजूद थे। हर साल की भांति इस साल भी रथ निर्माण के लिए करीब 10 हजार घन फिट की लकड़ी की जरूरत है। ऐसे में करीब 4 हजार घन फिट का लकड़ी लाया गया है।

संपूर्ण रथ निर्माण के लिए 490 पीस लकड़ी की जरूरत होगी, ऐसे में पहले पड़ाव में 215 पीस लकड़ी लाया गया है। वहां पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि समय बीतने के साथ रथ निर्माण का कार्य आगे बढ़ेगा। बाकी की लकड़ी धीरे-धीरे लाया जाएगा। कोविड गाइडलाइन के तहत ही तमाम रथ काठ की चिराई का कार्य चलेगा। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, असन, फसी आदि लकड़ी को रथ निर्माण के लिए लाया गया है।

राजस्थान में आंशिक लॉकडाउन के चलते भय का माहौल, प्रवासी श्रमिकों को सता रही है ये चिंता

जयपुर । कोरोना महामारी की दूसरी लहर में बढ़ रही संक्रमितों की संख्या, अस्पतालों में लगी लंबी कतारों और आंशिक लॉकडाउन के चलते भय का माहौल है। राजस्थान में अन्य राज्यों के मजदूर एक बार फिर पलायन करने लगे हैं। प्रदेश के भी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में रोजगार के लिए आए श्रमिक अपने घर लौट रहे हैं। अपने घर लौटते श्रमिकों को चिंता इस बात की है कि कहीं पिछले साल की तरह संपूर्ण लॉकडाउन लगा तो भूखे-प्यासे पैदल नहीं चलना पड़े। कोविड की गाइडलाइन के निर्देशों के तहत सरकार ने निर्माण कार्य, बाजार और फैक्ट्रियां बंद करा दी । होटलों में अब बाहर से लोग आ नहीं रहे। इस कारण लोग अपने घर की तरफ पलायन करने लगे हैं । अपने शहर-गांव जाने के लिए लोगों की कतारें बसों व ट्रेन के इंतजार में नजर आ रही है। इसी तरह गुजरात और दिल्ली में रोजगार के लिए गए राजस्थान के सिरोही, बांसवाड़ा, जालौर, डूंगरपुर जिलों के लोग बड़ी संख्या में वापस अपने घर आ रहे हैं।

मनमाना किराया वसूल रहे हैं चालक - बांसवाड़ा से राजस्थान आने वालों की रतनपुर बॉर्डर पर भीड़ नजर आ रही है। यही हाल दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से आने वालों का है। अपने घर वापस आने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट देखने के बाद प्रदेश की सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जाने वालों की बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भीड़ दिखाई दे रही है। हालांकि इस बार राहत की बात यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में यह बंद हो गए थे। हर दिन बिगड़ रहे हालातों के बीच निजी बस संचालक दो से तीन गुना किराया वसूल रहे हैं। जो निजी बसें पहले शहरों से गांवों के बीच चलती थी, वे अब बॉर्डर पार कर दूसरे राज्यों में जा रही है । इसके लिए चालक अपनी इच्छा से किराया वसूल रहे हैं।

ट्रेनों में लंबी वेटिंग, सरकारी बसों का संचालन हुआ कम- इसका मुख्य कारण ट्रेनों में लंबी वेटिंग और सीमित संख्या होना है। सरकारी बसों का संचालन कम होने की वजह से भी निजी बस संचालक मनमानी कर रहे हैं। एक यात्री की सीट पर दो सवारी बिठा रहे हैं। राजस्थान रोड़वेज की अब 700 बस चल रही है, जबकि दो माह पहले तक 1300 बसें चल रही थी । रोडवेज प्रबंधन का कहना है कि भय के कारण चालक ड्यूटी नहीं आ रहे । रोड़वेज के सीएमडी राजेश्वर सिंह हालात पर निगरानी रख रहे हैं। राजस्थान रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों का संचालन भी कम हुआ है। प्रदेश के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि लोगों को बसों की कमी नहीं आने दी जाएगी । जो भी जाना चाहेगा उसे वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे, वैसे राजस्थान सरकार हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

बिहार, प.बंगाल व यूपी जाने वालों की संख्या ज्यादा- राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, अलवर, राजसमंद व कोटा में काम करने वाले श्रमिक व अन्य लोगों में बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तरप्रदेश जाने वालों की संख्या ज्यादा है। अन्य शहरों से लोग जयपुर आ रहे हैं और फिर यहां से पटना, गोरखपुर, लखनऊ, हावड़ा, कलकत्ता, आगरा व मथुरा जा रहे हैं । सामान्य दिनों में जयपुर से इन शहरों का किराया 600 से 1100 रूपए तक था। अब निजी बस संचालक 1300 से 1800 रूपए तक वसूल रहे हैं। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉ.रघु शर्मा का कहना है कि सरकार ने लोगों के लिए चिकित्सा व अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी है। किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।

पहले कांग्रेस, फिर वामपंथी और अब तृणमूल के वर्चस्व वाले सूबे में भगवा झंडा

कोलकाता । अधिक समय नहीं बीते हैं। दो वर्ष पहले यहां तक कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी भाजपा नेताओं के बयान को याद करें। वे कहते थे-चुनाव प्रचार के लिए भाजपा को मंच, कुर्सी, लाउडस्पीकर देने को डेकोरेटर, वेंडर तैयार नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि होटलों और गेस्टहाउस तक में कमरे किराये पर नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि, तृणमूल कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता धमका रहे हैं। हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम मेदिनीपुर जिले में सभा हुई थी और उनके लिए मंच तैयार करने को कोलकाता से डेकोरेटर को ले जाया गया था और पंडाल का एक हिस्सा धराशाई हो गया था। इसके बाद से अन्य राज्यों से भाजपा को सभा के लिए मंच व पंडाल तैयार करने हेतु डेकोरेटर व कारीगर बुलाने पड़ रहे थे। दीवार लेखन तो दूर लोग भाजपा का झंडा लगाने से भी डरते थे।

लोकसभा चुनाव के बाद से बदली स्थिति- 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से स्थिति तेजी से बदलने लगी। कभी कांग्रेस के राज में वामपंथियों को झंडा लगाने से भय होता था तो वामपंथियों के राज में पहले कांग्रेस और फिर तृणमूल के साथ वही सलूक होता था। वामपंथियों के राज में तो माकपा को वोट नहीं मिलने पर हाथ तक काट लेने की घटना हुई थी। अब तृणमूल नेता भी हाथ काटने की धमकी दे रहे हैं। परंतु, तृणमूल कांग्रेस जब सत्ता में आई तो लोगों को लगा था कि अब स्थिति बदलेगी। परंतु, ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज भी ग्रामीण इलाकों में लोग कहते हैं कि पिछले आठ वर्षो से उन्हें वोट नहीं देने दिया जा रहा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर कोई कार्यकर्ता कैसे विपक्षी दल का झंडा उठाएगा। अब बंगाल में सियासी रंग काफी बदल गया है। लोग भाजपा के झंडा ही नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अब तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समक्ष भी जय श्रीराम के नारे बुलंद कर दे रहे हैं।

बिना भय के लोग लगाने दे रहे हैं झंडे व बैनर- लोग बिना भय के अपने घरों पर दीवार लेखने व पोस्टर-बैनर लगाने की अनुमति दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह की सभा के लिए अपनी जमीन देने पर पूर्व मेदिनीपुर जिले के कांथी के सुशील दास को जेल में डाला गया था।

भाजपा नेताओं को नई जिम्मेवारियां, प्रदेश उपाध्यक्ष बने विरेन्द्रजीत, शाम चौधरी

जम्मू । जमीनी सतह पर संगठनात्मक गतिविधियों को तेजी देने की मुहिम के तहत प्रदेश भाजपा ने पार्टी नेताओं को नई जिम्मेवारियां देते हुए सिख नेता विरेन्द्रजीत सिंह व पूर्व विधायक शाम चौधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है।

प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र रैना ने यह फैसला संगठन महामंत्री अशोक कौल व पार्टी के अन्य कुछ नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद लिया। पार्टी ने पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा व तारिक अहमद कीन को प्रदेश सचिव मनोनीत किया है। वहीं गुरदीप सिंह खालसा को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का संयोजक बनाया गया है। पूर्व विधायक गारू राम भगत को भी मोर्चा प्रधान बनाया गया है। बनी के पूर्व विधायक जीवन लाल को भाजपा पहाड़ी जिला का प्रधान बनाया गया है। भाजपा पहाड़ी जिले में कठुआ जिले के बसोहली, बिलावर व बनी इलाके आते हैं।

नई नियुक्तियां करने के बाद रविन्द्र रैना ने उम्मीद जताई कि पार्टी के ये वरिष्ठ नेता अपने अनुभव की सहायता से जम्मू कश्मीर में भाजपा को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने में सहयोग देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भाजपा लोगों को सशक्त बनाने के लिए कार्रवाई कर रही है। ऐसे में नेता जमीनी सतह पर पार्टी व लोगों के बीच समन्वय बनाकर उनके मसलों को हल करवाने की दिशा में कार्रवाई करे। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात में नए पदाधिकारी लोगों को जल्द कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित करें। प्रदेश भाजपा इस समय बूथ स्तर पर मजबूत होने की दिशा में कार्रवाई कर रही है। ऐसे में अब जम्मू संभाग में शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलनों के आयोजनों के बाद वरिष्ठ नेताओं को नई जिम्मेवारियां देकर आने वाले समय की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी हो रही है।

भाजपा ने कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर जारी किया

प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर 0191-3568199 जारी किया है। इसके अलावा bjphelplinejk@gmail.com पते से अपना ईमेल भी सार्वजनिक किया है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने बुधवार को त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजयुमो प्रधान अरूण जम्वाल, हेल्थ एंड मेडिकल सेल के संयोजक पुनीत महाजन, प्रदेश कार्यकारी सदस्य नितिश महाजन व अंकित महाजन की मौजूदगी में ये हेल्पलाइन नंबर व ईमेल आईडी जारी किया।

Cardi B के गाने पर पूल साइड पर डांस करती दिखीं

जाह्नवी कपूर

वीडियो वायरल

महाराष्ट्र में लॉकडाउन के चलते स्टार्स अपने घरों में ही बंद हो गए हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर फैन्स के लिए एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें जाह्नवी का एकदम नया और मजेदार अंदाज दिख रहा है. वीडियो में जाह्नवी काफी खुश भी नजर आ रही है और एक्ट्रेस की खुशी की मुख्य वजह है कि वह अपनी दोस्त के साथ डांस कर रही हैं.

जाह्नवी कपूर ने डांस के लिए अमेरिकन रैपर कार्डि बी का गाना चुना है. वीडियो को शेयर करते हुए जाह्नवी कपूर ने लिखा, 'फिल्मफेयर का स्टेज मिस कर रही हूं इसलिए फिलहाल पूलसाइड पर करना होगा.' जाह्नवी के हैशटैग से भी साफ हो रहा है कि वह फिल्मफेयर का बहुत मिस कर रही हैं. जाह्नवी की इस वीडियो को उनकी इंस्टा फैमिली भी काफी पसंद कर रही है.

ये कोई पहली बार नहीं है जाह्नवी कपूर लगातार इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर रही हैं.

जाह्नवी कपूर अभी कुछ दिन पहले वैकेशन के लिए दोस्तों के साथ मालदीव गई थीं. यहां से उन्होंने बिकिनी और स्विमसूट में तस्वीरें भी शेयर की थीं. जाह्नवी इन तस्वीरों में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. जाह्नवी ने साल 2018 में फिल्म धड़क से बॉलीवुड में कदम रखा था. फिल्म में वह इशान खट्टर के सामने नजर आई थीं. इसके बाद उनके करियर का ग्राफ ऊपर बढ़ता गया और फिल्म गुंजन सक्सेना में उनकी अदाकारी की खूब तारीफ भी हुई.

बॉलीवुड एक्टर जाह्नवी कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में जाह्नवी अपनी दोस्त के साथ डांस करती नजर आ रही है. एक्ट्रेस के फैन्स को ये वायरल वीडियो काफी पसंद आ रहा है.

करीना कपूर

ने मां बबीता को किया बर्थडे विश, कहा- मैं और लोलो हमेशा करेंगे परेशान

बॉलीवुड (Bollywood) एक्ट्रेस करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) आज यानी मंगलवार को अपनी मां और एक्ट्रेस बबीता कपूर (Babita Kapoor) का जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर फैंस के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी बबीता को बधाइयां दे रहे हैं. ऐसे में करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर बबीता कपूर के लिए एक पोस्ट शेयर किया है.

करीना ने अपने इंस्टाग्राम (Instagram) पर कुछ फोटो पोस्ट की है. जिसमें करीना और करिश्मा (Karisma Kapoor) के साथ बबीता कपूर नजर आ रही हैं. बबीता कपूर बीच में खड़ी हैं और बेटियां उनके दोनों तरफ हैं. इसके अलावा करीना ने बबीता कपूर की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की है. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए करीना कपूर खान ने कैप्शन दिया, हैप्पी बर्थडे मां, आप हमारी ताकत हैं, हमारी पूरी दुनिया हैं. मैं और लोलो हमेशा ही आपको परेशान करते रहेंगे.करीना ने अपनी पोस्ट पर बड़ी बहन करिश्मा कपूर को भी टैग किया है. आपको बता दें कि करीना कपूर के इस पोस्ट पर रिद्धिमा कपूर और मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने भी कमेंट किया है. मनीष ने बबीता को विश करते हुए लिखा- हैप्पी बर्थडे बबीता जी.वहीं, बात करें करीना और करिश्मा की मां बबीता कपूर के करियर के बारे में तो उनके पिता हरि शिवदासानी भी एक एक्टर थे. बबीता ने अपने करियर की शुरुआत साल 1966 में फिल्म दस लाख से की थी. साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म राज से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सफलता मिली. इसके बाद उन्होंने तुमसे अच्छा कौन, पहचान,हसीना मान जाएगी, अनजाना, कल आज और कल और जीत जैसी कई फिल्मों में काम किया. फिर साल 1971 में बबीता ने रणधीर कपूर से शादी कर घर बसा लिया. शादी के बाद बबीता ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अपना घर संभाला.

शिल्पा शेट्टी ने कहा- लॉकडाउन में स्ट्रेस से दूर रहना है तो योगा करें, फिट रहें

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने सोमवार को लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंधों के कारण तनाव के बीच फिट और स्वस्थ रहने की आवश्यकता पर जोर दिया. अभिनेत्री ने प्रतिबंधित मूवमेंट्स के प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के शरीर को सुरक्षित रखने के महत्व पर भी प्रकाश डाला.

शिल्पा ने ट्वीट करते हुए कहा, बढ़ते मामलों के कारण लॉकडाउन और अन्य प्रतिबंध बहुत अधिक तनाव पैदा कर सकते हैं. लेकिन हमें एकजुट रहना होगा और हमें वही करना होगा, जो हमें करने की आवश्यकता है. सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे अपने शरीर प्रतिबंधित मूवमेंट्स से होने वाले प्रभावों के शिकार न हों.

इस दौरान लोगों को प्रोत्साहित करते हुए शिल्पा ने हैशटैग मंडे मोटिवेशन का भी उपयोग किया.

शिल्पा ने हमारी प्रतिरक्षा के लिए मांसपेशियों और जोड़ों को लचीला और चुस्त रखने को लेकर जोर दिया और इसे काफी महत्वपूर्ण भी बताया. शिल्पा ने यह भी बताया कि इसके लिए योग कितना जरूरी है और यह हमारी मांसपेशियों को किस तरह से मजबूत करता है.

अभिनेत्री ने लोगों को नसीहत देते हुए कहा कि सुरक्षित रहें और सामाजिक दूरी बनाए रखें.

प्रियंका चोपड़ा को गलत नाम से पुकारते थे हॉलीवुड के लोग, एक्ट्रेस ने ऐसे सिखाया सही तरीका

बॉलीवुड से हॉलीवुड का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अब एक ग्लोबल आइकॉन बन चुकी हैं. हाल में वह अपनी ऑटोबायोग्राफी अनफिनिश्ड को लेकर काफी चर्चा में रही. उन्होंने अपनी इस किताब ने में अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, निक जोनास के साथ रिलेशनशिप और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के सफर के बारे में कई अहम खुलासे किए.

प्रियंका चोपड़ा अब एक बार फिर से चर्चा में हैं. वह कबीर बेदी के मेमॉयर स्टोरीज आई मस्ट टेल के लॉन्च के मौके पर में वीडियो कॉल के जरिए शामिल हुई थी. इस दौरान दोनों ने अपने हॉलीवुड में काम करने के अनुभवों को शेयर किया. तभी प्रियंका चोपड़ा ने उन्हें बताया कि शुरुआत में हॉलीवुड में लोग उनका नाम ठीक से नहीं ले पाते थे.

भारतीय कलाकारों को बदलना पड़ता था नाम

कबीर बेदी ने बॉलीवुड हंगामा को बताया कि हॉलीवुड में उन दिनों एशियाई या भारतीय कलाकारों के लिए किरदार नहीं लिखे जाते थे. अमेरिकी ऑडियंस को विदेशी दिखने वाले रोल ही भारतीय किरदारों को मिलते थे. उन्होंने बताया कि उन्होंने इंडियन, मोरक्कन और कई विदेशी किरदार निभाए. उन्होंने ये भी बताया कि पहले भारतीय कलाकारों को हॉलीवुड में काम करने के लिए अपने नाम बदलने पड़ते थे.

यहां देखिए प्रियंका चोपड़ा का वीडियो-

बुलाते थे शापरा-शापरा

वहीं, प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि अब हॉलीवुड में ऐसा नहीं होता है. हॉलीवुड में सक्सेस हासिल करने के लिए अब नाम बदलने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा,हॉलीवुड में काम करने के लिए मुझे नाम नहीं बदलना पड़ा. हालांकि कई लोग उन्हें शापरा-शापरा पुकारते थे. लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम कैसे लेना है. अगर आप ओपरा बोल सकते हैं तो चोपड़ा भी बोल सकते हैं. ये मुश्किल नहीं है.

आरसीबी में आकर पहले ही दिन से मुझे घर जैसा महसूस होने लगा, ऑलराउंडर का दावा

मुंबई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सेवल ने कहा है कि जब से वह भारत में फ्रेंचाइजी के साथ जुड़े हैं वे घर जैसा महसूस कर रहे हैं। मैक्सवेल जो पिछले कुछ आइपीएल सीजनों में बल्ले के साथ खराब फॉर्म से गुजरे हैं, उन्होंने आरसीबी के लिए खेलते हुए तहलका मचाया हुआ है। सिर्फ तीन मैचों में उन्होंने 176 रन जड़ दिए हैं, जिसमें दो अर्धशतकीय पारियां भी शामिल हैं।

आरसीबी के ट्विटर हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो में ग्लेन मैक्सवेल ने कहा है, वानखेड़े में यहां स्थितियां थोड़ी भिन्न हैं। यहां कुछ उच्च स्कोर बनाए गए हैं, इसलिए हमारे बल्लेबाजी समूह के लिए, यह रोमांचक होने वाला है। हम मैदान पर जाकर उन हाई-स्कोरिंग मैचों की तरह खेलना जारी रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पहले ही दिन से घर पर हूं, कोचिंग स्टाफ ने भी मुझे आरसीबी में बहुत सपोर्ट किया है। आरसीबी मौजूदा सत्र में सभी तीन मैच जीतने में सफल रही है और यह गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी। आइपीएल के इस नए सीजन में आरसीबी ही एकमात्र टीम है, जिसने अभी तक अपने सभी मुकाबले जीते हैं। इस बारे में मैक्सवेल ने कहा, यह विराट के कंधों में से एक की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। उन्हें मैदान पर बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, यह नियंत्रित करने के लिए कि फील्डरों को किन स्थितियों में रहने की जरूरत है, एक बात यह है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैक्सवेल ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ आरसीबी के आखिरी मैच में 78 रनों की पारी खेली थी और वह अपने फॉर्म को जारी रखने की उम्मीद कर रहे होंगे। केकेआर के खिलाफ मैच के बाद, आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि मैक्सवेल पानी के लिए एक बतख की तरह आरसीबी को ले गए थे। आरसीबी के खाते में इस समय 6 अंक हैं और टीम दूसरे स्थान पर है।

पिछले साल की फिसड्डी टीम इस बार पहुंची टॉप पर

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आइपीएल के 13वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके टॉप 4 में आने के लिए तरस गई थी, क्योंकि पिछले साल एमएस धौनी की कप्तानी वाली चेन्नई की टीम सातवें स्थान पर रही थी। यहां तक कि आइपीएल के 14वें सीजन का पहला मुकाबला भी चेन्नई सुपर किंग्स हार गई थी, लेकिन चार मैचों के बाद चेन्नई की टीम आइपीएल 2021 की अंकतालिका में शीर्ष पर है।

चेन्नई सुपर किंग्स ने आइपीएल के 14वें सीजन के अपने पहले चार मैचों में से तीन मैच जीत लिए हैं। 4 मैचों में 6 अंक और +1.142 के बेहतर नेट रन रेट की वजह से सीएसके प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर है। दूसरे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। आरसीबी के खाते में भी तीन मैचों में तीन जीत के साथ 6 अंक हैं, लेकिन सीएसके के नेट रन रेट विराट कोहली की कप्तानी वाली बैंगलोर की टीम से बेहतर है। यही वजह से आरसीबी दूसरे नंबर पर विराजमान है। आइपीएल 2021 की अंकतालिका में तीसरे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स का है, जिसके खाते में भी 6 अंक है, लेकिन नेट रन रेट दिल्ली की टीम का सीएसके तो छोड़िए, आरसीबी से भी खराब है। वहीं, मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पर है, जिसने दो मैचों में जीत हासिल की है और इतने ही मैच गंवाए हैं। चार अंकों के साथ टीम चौथे स्थान पर है। पांचवें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम है, जिसने बुधवार को अपनी पहली जीत हासिल की है।

छठे नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स का नंबर है, जबकि सातवें स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है। आठवें और सबसे आखिरी पायदान पर पंजाब किंग्स है, जिसके खाते में भी सिर्फ दो ही अंक है। हालांकि, अगर गुरुवार यानी आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मैच के बाद अंकतालिका में और भी बदलाव हो सकता है। आरसीबी के जीतने पर आरसीबी नंबर वन बन जाएगी, जबकि राजस्थान के जीतने पर टीम पांचवें या चौथे स्थान पर पहुंच सकती है।

पाकिस्तान की टीम का विजय रथ जारी, अब जिंबाब्वे को 11 रन से दी मात

हरारे। साउथ अफ्रीका को सीमित ओवरों की सीरीज में उसी की सरजमीं पर हराने के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे के दौरे पर गई, जहां टीम ने पहला ही मुकाबला अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की नाबाद अर्धशतकीय पारी की बदौलत बुधवार को यहां पहले टी20 मैच में मेजबान जिंबाब्वे को 11 रन से शिकस्त देकर सीरीज में बढ़त हासिल की।

पाकिस्तान की टीम ने रिजवान के नाबाद 82 रन से सात विकेट पर 149 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में जिंबाब्वे की टीम ने सात विकेट पर 138 रन बना पाई। एक समय मुकाबला टक्कर का लग रहा था, लेकिन मेजबान टीम जीत की लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई। दूसरा मैच अब शुक्रवार 23 अप्रैल को हरारे के ही हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। तीसरा मैच भी इसी मैदान पर आयोजित होगा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने कप्तान बाबर आजम का विकेट दूसरे ही ओवर में गंवा दिया था और फखर जमां भी 13 रन बनाकर आउट हो गए थे लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज और टीम के उपकप्तान मोहम्मद रिजवान एक छोर पर डटे रहे और टीम को अच्छा स्कोर बनाने में मदद की। रिजवान ने 61 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और एक छक्का जमाया और 82 रन की पारी खेली।उधर, जिंबाब्वे की टीम 150 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी और उसने तीसरे ही ओवर में दो विकेट खो दिए। इसके बाद कोई बड़ी साझेदारी नहीं बन सकी।

सीएसके ने केकेआर को 18 रन से हराया

● रसेल और कमिंस ने 56 बॉल पर 120 रन बनाए, फिर भी हारी कोलकाता

चाहर ने लिए 4 विकेट

मुंबई। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत की हैट्रिक लगा ली है। टीम ने आईपीएल 2021 के 15वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से शिकस्त दी। इस जीत के साथ CSK पॉइंट टेबल में नंबर-1 पर पहुंच गई है। 221 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी कोलकाता टीम ने 31 रन पर 5 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद आंद्रे रसेल और पैट कमिंस ने मिलकर 56 बॉल पर 120 रन बनाए, लेकिन टीम को नहीं जिता सके। रसेल ने 22 बॉल पर 54 और कमिंस ने 34 बॉल पर नाबाद 66 रन बनाए।

आखिर में पैट कमिंस ने नाबाद 66 रन की पारी खेली। टीम ऑलआउट होने के कारण वे जीत नहीं दिला सके। मैच खत्म होने तक कोलकाता को 5 बॉल प 19 रन की जरूरत थी। चेन्नई के लिए दीपक के अलावा लुंगी एनगिडी ने 3 और सैम करन ने एक विकेट लिया।

आंद्रे रसेल और पैट कमिंस की पारी भी कोलकाता को नहीं जिता सकी: 221 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी कोलकाता टीम की शुरुआत खराब रही। टीम ने पहले ही ओवर में एक विकेट गंवा दिया।

ओपनर शुभमन गिल एक बॉल खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दीपक चाहर ने उन्हें एनगिडी के हाथों कैच आउट कराया।

दीपक ने 17 के स्कोर पर चयक्रटीम को दूसरा झटका दिया। उन्होंने ओपनर नीतीश राणा को भी 9 रन पर पवेलियन भेज दिया।

31 रन पर आते-आते कोलकाता की आधी टीम पवेलियन लौट गई। दीपक ने 4 खिलाड़ियों को शिकार बनाया।

इस तेज गेंदबाज ने शुभमन गिल, नीतीश राणा, ओएन मोर्गन और सुनील नरेन को आउट किया। 5वां झटका लुंगी एनगिडी ने दिया।

सीजन का पहला मैच खेल रहे एनगिडी ने राहुल त्रिपाठी को 8 रन पर पवेलियन भेजा। CSK टीम के कप्तान और विकेटकीपर धोनी ने 3 कैच लपके।

धोनी ने राणा, त्रिपाठी और मोर्गन का कैच लिया। लगातार विकेट गिरने के बीच दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसेल ने 7वें ओवर में टीम का स्कोर 50 के पार पहुंचाया।

रसेल और कार्तिक ने छठे विकेट के लिए 39 बॉल पर 81 रन की पार्टनरशिप की। कोलकाता को 112 के स्कोर पर छठा झटका लगा।

फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर सैम करन ने रसेल को क्लीन बोल्ड किया। टीम 146 के स्कोर पर 7वां विकेट गंवाया। कार्तिक को एनगिडी ने LBW किया।

एनगिडी ने कोलकाता टीम को 8वां झटका 176 के स्कोर पर दिया। उन्होंने कमलेश नागरकोटी को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा।

पैट कमिंस एक छोर संभाले रहे और लगातार बड़े हिट मारते रहे। 18वें ओवर में उन्होंने IPL में अपनी दूसरी फिफ्टी लगाई। आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 20 रन की जरूरत थी और एक विकेट बाकी था। तभी 2 रन लेने के चक्कर में प्रसिद्ध कृष्णा रनआउट हो गए और KKR टीम ने मैच गंवा दिया।

रसेल को जीवनदान मिला

10वें ओवर की तीसरी बॉल पर आंद्रे रसेल को जीवनदान मिला। शार्दूल का ओवर था और बाउंड्री पर मोइन अली ने कैच छोड़ा। इस समय रसेल 35 रन बनाकर खेल रहे थे।

धोनी बोले-अच्छा स्कोर होने के बाद बड़ा दिल रखना जरूरी, रसेल ने कहा- टॉप ऑर्डर की नाकामी की वजह से हारे

मुंबई। आईपीएल में खेले गए 15वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 18 रन से शिकस्त दी। 221 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी चयक्र19.1 ओवरों में 202 रन ही बना सकी। जीत के बाद CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि अगर KKR 20 ओवर तक बैटिंग करती तो शायद जीत सकती थी।

उन्होंने कहा कि 15-16 ओवर से तेज गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच टक्कर होती है। इस समय आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वही टीम जीतती है, जो अपनी योजना को बेहतर तरीके से लागू कर पाती है। आप शुरुआत में ज्यादा विकेट नहीं ले सकते हैं। सभी टीमों में अच्छे हिटर्स हैं। सूखी और टर्निंग पिच पर हमारे पास एकमात्र विकल्प जडेजा थे। अगर उनके पास विकेट होते तो स्थिति अलग हो सकती थी। मैंने टीम के खिलाड़ियों से कहा था कि हमने अच्छा स्कोर किया है, लेकिन हमें विनम्र रहने की जरूरत है। जब इस पिच पर आप रन बना सकते हैं, तो विपक्षी खिलाड़ी भी बना सकते हैं।

धोनी ने बल्लेबाजों की तारीफ की

धोनी ने बल्लेबाजों की तारीफ की। इस मैच में गायकवाड़ ने 42 गेंदों पर 65 रन बनाए, जबकि डुप्लेसिस ने 60 गेंदों पर 95 रन बनाए। धोनी ने गायकवाड़ का जिक्र करते हुए कहा कि ऋतुराज पिछले सीजन में अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। लेकिन इस सीजन के शुरुआती मैचों में रन नहीं बना पा रहे थे। हालांकि उनके अंदर आत्मविश्वास दिख रहा था। अच्छा है कि इस मैच में उन्होंने बेहतरीन पारी खेली।

मॉर्गन ने कार्तिक, कमिंस और रसेल की तारीफ की

केकेआर के कप्तान इयोन मॉर्गन ने हार के बाद कहा कि जब 5.2 ओवर में 5 विकेट गिर गए थे, तब उन्होंने सोचा भी नहीं था टीम की जीतने की भी उम्मीद है। लेकिन आंद्रे रसेल, दिनेश कार्तिक, पैट कमिंस बल्लेबाजी से मैच में वापसी हुई और हम जीत के करीब पहुंच पाए। पॉवर प्ले के दौरान हमने विकेट खो दिए थे। हम मैच में कहीं भी नहीं दिख रहे थे। लेकिन हमारे मध्यक्रम और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन पारी खेली औप टीम को मैच में वापस लाए। हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फेल रहे। इस मैच में दिनेश कार्तिक ने 24 गेंदों पर 40 रन, आंद्र रसेल ने 22 गेंदों पर 54 रन और पैट कमिंस ने 34 गेंदों पर 66 रन बनाए।

सुपरलीग पर किक: इंग्लैंड और इटली के 10 क्लब हटे, गठन से पहले ध्वस्त प्रस्तावित लीग

नई दिल्ली। यूरोपीय फुटबॉल में हड़कंप मचाने के बाद प्रस्तावित सुपरलीग एक भी किक लगे बगैर ध्वस्त हो गई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग (ईपीएल) के छह क्लबों आर्सेनल, चेल्सी लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटेनहम हॉटस्पर ने लीग से हटने की घोषणा कर दी है। उसके बाद इटली के क्लबों एटलेटिको मैड्रिड, इंटर मिलान, एसी मिलान और युवेंटस ने भी कदम पीछे हटा लिया है।

अब अधिकृत रूप से केवल स्पेन के रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ही लीग में शेष बचे हैं। सुपरलीग के नए अध्यक्ष रियल मैड्रिड क्लब के प्रमुख फ्लोरेंटिनो पेरेज हैं। यूएफा ने भी धमकी दी थी कि वह सुपर लीग में शामिल खिलाड़ियों को अगले साल होने वाली यूरोपियन चैंपियनशिप और विश्व कप में खेलने से प्रतिबंधित कर देगा। इटली के क्लबों में एटलेटिको और इंटर मिलान की घोषणा के बाद एसी मिलान ने भी लीग छोड़ने की घोषणा कर दी।

समर्थकों और सरकार का भी दबाव

इंग्लिश क्लबों पर समर्थकों के विरोध का बड़ा दबाव पड़ रहा था। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे दी थी। सरकार ने इस लीग के गठन के खिलाफ कानून बनाने की भी चेतावनी दी थी। एक दिन पहले यूएएफा के अध्यक्ष एलेक्जेंडर कैफेरिन ने इन सभी क्लबों से चैंपियंस लीग का हिस्सा बने रहने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि अपनी गलती मानना अच्छी बात है कि उन्होंने गलती तो की थी। वे फिर से हमारे साथ हैं। हम फिर से एकता पर जोर देंगे और साथ-साथ आगे बढ़ेंगे और खेल का लुत्फ उठाएंगे जैसे पहले उठाते रहे हैं।

क्लबों में हो गया था मतभेद

इंग्लैंड, स्पेन और इटली के कुल 12 शीर्ष यूरोपीय टीमों ने सोमवार को घोषणा की कि वे अपनी लीग बनना चाहते हैं। सबसे पहले मैनचेस्टर सिटी ने पुष्टि की कि वो इस लीग से हट रही है। इंग्लैंड के अन्य पांच क्लबों ने भी हटने की पुष्टि की। सुपर लीग क्लबों के भीतर विभाजन भी मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गार्डियोला के साथ बढ़ गया जिन्होंने कहा कि सुपर लीग खेल की अखंडता और मूल्यों को नुकसान पहुंचाएगा। लिवरपूल के मैनेजर जर्गेन क्लोप ने भी अपने क्लब के मालिकों के कार्यों के बारे में चिंता व्यक्त की है। चेल्सी, जो रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच के स्वामित्व में है, ने कहा कि यह केवल पिछले सप्ताह सुपर लीग समूह में शामिल हो गया। हमारे पास अब इस मामले पर पूरी तरह से विचार करने का समय है और फैसला किया है कि इन योजनाओं में हमारी निरंतर भागीदारी क्लब, हमारे समर्थकों या व्यापक फुटबॉल समुदाय के सर्वोत्तम हित में नहीं होगी।

नए प्रारूप की योजना

इस बीच यूरोपियन सुपर लीग ने घोषणा की कि यह इस परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए कदम उठाएगा। रिपोर्टों के अनुसार, सुपर लीग ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, हम परियोजना को फिर से किसी रूप में शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त कदमों पर पुनर्विचार करेंगे। स्पेन और इटली के क्लबों ने आरोप लगाया है कि इंग्लिश क्लबों को यह कदम दबाव में उठाना पड़ा है।

विश्व युवा चैंपियनशिप: भारतीय मुक्केबाजों ने 10 पदकों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा, 11 पदक तय

नई दिल्लाी। सात महिलाओं सहित भारत के आठ मुक्केबाजों ने पोलैंड के किल्से में चल रही विश्व युवा चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई जो देश के लिए आयु वर्ग की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में अभूतपूर्व उपलब्धि है। आठ खिलाड़ियों के फाइनल में जगह बनाने के अलावा तीन अन्य मुक्केबाजों ने कांस्य पदक भी जीते जिससे भारत ने कम से कम 11 पदक सुनिश्चित करके 2018 में हंगरी में 10 पदक जीतने के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पीछे छोड़ा। महिलाओं में गीतिका (48 किग्रा), बेबीरोजिसाना चानू (51 किग्रा), विंका (60 किग्रा), अरुंधति चौधरी (69 किग्रा), पूनम (57 किग्रा), थोकचोम सनामाचा चानू (75 किग्रा) और अल्फिया पठान (+81 किग्रा) ने फाइनल में जगह बनाई। गीतिका ने इटली की एरिका प्रिसकियानदारो को 5-0 से हराया जबकि विंका ने चेक गणराज्य की वेरोनिका गाजदोवा को 4-1 से शिकस्त दी। अरुंधति को उज्बेकिस्तान की खादिचाबोनू को सर्वसम्मत फैसले में 5-0 से हराने में अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ी। गत एशियाई युवा चैंपियन बेबीरोजिसाना ने भी इटली की एलेन अयारी को 5-0 से हराया। पूनम ने उज्बेकिस्तान की सितोरा तुर्दिबेकोवा को 5-0 से हराया। सनामाचा ने पोलैंड की दारिया परादा को 4-1 से हराया। अल्फिया ने कड़े मुकाबले में पोलैंड की ओलीविया तोबोरेक को 3-2 से हराया। पुरुष वर्ग

में सिर्फ सचिन (56 किग्रा) ने खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया। सचिन ने इटली के माइकल बालदासी को हराया। वह फाइनल में कजाखस्तान के येरबोलात सेबिर से भिड़ेंगे। जबकि अंकित नरवाल (64 किग्रा), विश्वामित्र चोंगथोम (49 किग्रा) और विशाल गुप्ता (91 किग्रा) को सेमीफाइनल में हार के साथ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

केकेआर के जख्मों पर नमक: कप्तान मॉर्गन पर भी ठोका गया 12 लाख का जुर्माना

मुंबई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बुधवार रात खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइटराइडर्स को चेन्नई सुपरकिंग्स के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। सीएसके से मिली हार के बाद केकेआर के कप्तान इयोन मॉर्गन पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आईपीएल ने बयान में कहा, 'कोलकाता नाइटराइडर्स के कप्तान इयोन मॉर्गन चेन्नई के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति रखने के आरोपी पाए गए। टीम का आईपीएल आचार संहिता के तहत इस सत्र का यह धीमी ओवर गति से जुड़ा पहला मामला है इसलिए 12 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।' आईपीएल के संशोधित नियमों के अनुसार धीमी ओवर गति के पहले मामले में टीम के कप्तान पर 12 लाख रुपये का जुर्माना किया जाता है। अगली बार इस तरह की गलती दोहराने पर एक मैच के लिए निलंबित भी किया जा सकता है।

आईपीएल के दिशानिर्देशों के अनुसार, टीम के कप्तान को धीमी ओवर रेट के लिए पहले मैच में 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरे मैच में, जुर्माना दोगुना (24 लाख रुपये) है, जबकि प्लेइंग इलेवन के प्रत्येक सदस्य पर मैच फीस का 25 प्रतिशत या 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा (जो भी कम हो)

जब सीजन में तीसरी बार अपराध किया जाता है, तो कप्तान को 30 लाख रुपये का शुल्क देना होगा और एक मैच का प्रतिबंध भी झेलना पड़ेगा, जबकि प्लेइंग इलेवन के बाकी सदस्यों पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। या मैच फीस का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) सीएसके ने फाफ डुप्लेसिस के नाबाद 95 रन और दीपक चाहर के चार विकेट की मदद से रात को केकेआर पर 18 रन से जीत दर्ज की थी। इस बड़े स्कोर वाले मैच में सीएसके ने तीन विकेट पर 220 रन बनाए, इसके जवाब में केकेआर 202 रन पर आउट हो गया।

राशिद खान का दावा- ये खिलाड़ी भविष्य में भारत के लिए बनेगा प्रोपर ऑलराउंडर

चेन्नई। सनराइजर्स हैदराबाद के स्पिनर राशिद खान का मानना है कि अभिषेक शर्मा भविष्य में भारत के लिए एक प्रोपर ऑलराउंडर बन जाएंगे। खलील अहमद और अभिषेक शर्मा के एक शानदार गेंदबाजी प्रयास ने यहां चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबद के लिए 19.4 ओवर में पंजाब किंग्स को 120 रनों पर रोक दिया। इसके बाद राशिद खान ने अभिषेक शर्मा की तारीफ की है।

जॉनी बेयरेस्टो और डेविड वार्नर की शानदार बल्लेबाजी के दम प हैदराबाद ने एक विकेट खोकर 121 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। मैच के बाद आइपीएल की वेबसाइट पर जारी वीडियो में राशिद खान ने अभिषेक शर्मा से कहा, 'आप भविष्य में भारत के लिए एक प्रोपर ऑलराउंडर बन जाएंगे जो अपनी टीम के लिए बहुत

सारे मैच खेलेंगे और जीतेंगे। आपमें बहुत क्षमता है। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी।

वहीं, अपने प्रदर्शन पर राशिद खान से अभिषेक शर्मा ने कहा, मैं गेंदबाजी का भरपूर अभ्यास कर रहा था। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच से पहले जब हम अपने पड़ाव में थे, तो कप्तान डेविड वार्नर ने मुझसे कहा कि आप पहले ओवर में गेंदबाजी करने जा रहे हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से नहीं सुना, इसलिए एक बार फिर इसकी पुष्टि की। मैंने आपसे इस भूमिका के बारे में बहुत कुछ पूछा, मुझे ह्मारी टीम के लिए काम करने का भी भरोसा था।

उन्होंने आगे बताया, लॉकडाउन के दौरान, हम घर पर थे। मेरे पिता मेरे बचपन के कोच हैं, वह बाएं हाथ के स्पिनर थे इसलिए मैंने लॉकडाउन के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। स्लाइडर जैसा वेरिएशन, मैंने उनसे सीखा है।

मुझे मैच में इसे लागू करने का भरोसा था। मुझे लगता है कि मैं इस गेंद को खेल के किसी भी स्तर पर खेल सकता हूं। 4 ओवर में अभिषेक शर्मा ने 24 रन दिए और 2 महत्वपूर्ण विकेट टीम के लिए हासिल किए।

गेंदबाजों के बाद चमके बेयरस्टो, सनराइजर्स ने दर्ज की पहली जीत

चेन्नई। सनराइजर्स हैदराबाद ने आखिरकार सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज की। डेविड वार्नर की अगुवाई में सनराइजर्स ने इस बार हर क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया और पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत हासिल की। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में पंजाब किंग्स के 121 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम ने जॉनी बेयरस्टो की अर्धशतकीय पारी के दम पर आठ गेंदें शेष रहते 9 विकेट से बाजी अपने नाम की।

पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन उसका यह फैसला सनराइजर्स के गेंदबाजों ने गलत साबित कर दिया। टीम ने 100 रन के अंदर अपने छह विकेट गंवा दिए। इसके बाद भी कोई खिलाड़ी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहा और पूरी टीम 19।4 ओवर में 120 रन पर ही ढेर हो गई। मयंक अग्रवाल (22) और शाहरुख़ खान (22) ने सर्वाधिक रन बनाये। वहीं हैदराबाद की तरफ से खलील अहमद ने सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ने

मजबूत शुरुआत दिलाई। दोनों ही खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 73 रन जोड़े। हालांकि वार्नर 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन बाद में केन विलियमसन (16*) और बेयरस्टो (63*) ने मिलकर टीम को पहली जीत दिला दी।